आज का सुविचार
जब दुःख अपनी चरम सीमा पर होता है, तब सुख ज्यादा दूर नहीं होता।
- महात्मा गाँधी

दैनिक
इंटीग्रेटेड ट्रेड

आईटीडीसी इंडिया ई-प्रेस | 2018 में स्थापित | ITDCNEWS.COM

डेवलपमेंट सेंटर न्यूज

आरएनआई नं.
MPHIN/2018/77221
डाक पंजीयन नं.
MP/BHOPAL/4-504/2020-22

वर्ष-5 अंक-42 भोपाल, गुरुवार 23 दिसम्बर, 2021, पृष्ठ-8, मूल्य-2 रुपए

पंचांग
मार्गशीर्ष शुक्ला
अष्टमी, गुरुवार 22
विक्रम, संवत 2078

मौसम

सूर्योदय/सूर्यास्त	6:56/5:38
वर्षा/बादल %	00 %
नमी %	23 %
वायु (किमी/घ.)	05
तापमान प्रातः/रात्रि (डिग्री से.)	25°/11°

स्वर्ण दर 24 कैरेट
प्रति 10 ग्राम/1तौला
₹ 49,755

शेयर सूचकांक

बीएसई	56930.56	+611.55
निफ्टी	16955.45	+184.60

गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा की ऑनलाइन कंपनियों को चेतावनी, अपने प्लेटफार्म से हटाएं नशे और हथियार जैसी आपत्तिजनक सामग्रियां

आईटीडीसी इंडिया ई-प्रेस/ आईटीडीसी न्यूज भोपाल

प्रदेश के जबलपुर जिले में ई-कामर्स कंपनी फ्लिपकार्ट द्वारा चाकू जैसा घातक हथियार बेचे जाने का प्रकरण सामने आने के बाद अब सरकार ने भी इस मामले में सख्त रुख अपनाया है। गृहमंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने इसका संज्ञान लेते हुए आनलाइन शापिंग कंपनियों को चेतावनी दी है कि वे अपने प्लेटफार्म से नशे और हथियार जैसी चीजों को जल्द से जल्द हटाएं। उन्होंने कहा कि जबलपुर में ई-कॉमर्स कंपनी को अपने प्लेटफॉर्म से चाकू और ऐसे अन्य आपत्तिजनक समान हटाने के आदेश दिए गए है। यह आदेश उन्हें भेज भी दिया है। संभवतः उन्होंने हटा भी दिए होंगे। अगर नहीं हटाए होंगे, तो हटवा देंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम मध्य प्रदेश में ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन और फ्लिपकार्ट को अपने प्लेटफॉर्म से नशे और हथियार से जुड़ी घातक सामग्री हटाने का आग्रह करते हैं, अन्यथा हमें इनके बारे में सोचना पड़ेगा। इसके साथ ही गृहमंत्री ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के माब लिंचिंग को लेकर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 1984 के सिख विरोधी दंगों में कांग्रेस के लोगों ने देश में मॉब लिंचिंग की शुरुआत की थी। तुष्टिकरण की राजनीति करने राहुल गांधी जी को चुनाव के समय उत्तर प्रदेश में तो मॉब लिंचिंग दिखाई दे रही है लेकिन केरल में नहीं, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं को बेरहमी से मारा गया।

संसद का विंटर सेशन समाप्त

लोकसभा-राज्यसभा की कार्यवाही तय समय से एक दिन पहले ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित

आईटीडीसी इंडिया ई-प्रेस/ आईटीडीसी न्यूज नई दिल्ली

संसद का विंटर सेशन आज समाप्त हो गया। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही तय समय से एक दिन पहले ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। विंटर सेशन 29 नवंबर को शुरू हुआ, जो 23 दिसंबर तक शेड्यूल्ड था। बताया जा रहा है कि दोनों सदनों में लगातार जारी हंगामे के चलते सत्र को जल्दी समाप्त करने का फैसला लिया गया। विपक्ष के हंगामे के बावजूद सदनों में कुछ अहम बिल पास हुए। वोटर ID को आधार कार्ड से जोड़ने वाला बिल मंगलवार को राज्यसभा में पास हुआ। बिल के खिलाफ विरोध जताते हुए विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया, जबकि तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने रिपोर्टर्स की टेबल पर रूलबुक फेंक दी, जिसके बाद उन्हें सदन से निलंबित कर दिया गया।

चुनाव कानून संशोधन विधेयक को लेकर भारी हंगामा हुआ

चुनाव कानून संशोधन विधेयक, 2021 संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुका है। इसमें मतदाता सूची से दोहराव को समाप्त करने के प्रावधान हैं। सदन में विपक्ष ने इस बिल का भी भारी विरोध किया था। विपक्षी नेताओं ने इसके खिलाफ सदन में नारेबाजी की और वेल में चले आए। इनकी मांग थी कि बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए। आखिरकार बिल का समर्थन करने वाले कई दलों के सदस्यों के साथ एक घंटे की चर्चा के बाद यह पास हुआ।

कांग्रेस के 6; टीएमसी, शिवसेना और लेफ्ट के 6 सांसद सस्पेंड

राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने निलंबित सांसदों के नाम की घोषणा की। इनमें कांग्रेस के 6 सांसद- फूलो देवी नेताम, छाया वर्मा, रिपुन बोरा, राजमणि पटेल, सैयद नासिर हुसैन, अखिलेश प्रसाद सिंह शामिल हैं। ममता बनर्जी की पार्टी ञ्रस्ष्ट से डोला सेन और शांता छेत्री को सस्पेंड किया गया है। इसके अलावा शिवसेना से प्रियंका चतुर्वेदी और अनिल देसाई शामिल हैं। वहीं CPM के एलाराम करीम और CPI के बिनॉय विश्वम भी निलंबित होने वाले सांसदों की लिस्ट में शामिल हैं।

केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग कर रहा विपक्ष

विपक्ष लखीमपुर खीरी केस में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग करता रहा। विपक्ष का आरोप है कि सरकार टेनी को बचा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी टेनी के इस्तीफे का मुद्दा लगातार उठाया। उनका कहना था कि केंद्र इस पर चर्चा से भाग रहा है। टेनी के इस्तीफे को लेकर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कई बार स्थगित हुई।

राज्यसभा के निलंबित 12 सांसदों को लेकर विपक्ष अड़ा

विंटर सेशन पहले दिन से ही हंगामेदार रहा। राज्यसभा के निलंबित 12 सांसदों के मामले को लेकर विपक्ष लगातार अड़ा रहा। विपक्षी नेताओं का कहना था कि यह निलंबन असंवैधानिक है। निलंबित सांसद भी हर दिन संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास धरना दे रहे। मालूम हो कि राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने मानसून सत्र के दौरान इन सांसदों को अनियंत्रित व्यवहार के लिए निलंबित कर दिया था।

राजस्थान में ओमिक्रॉन के 4 नए केस मिले

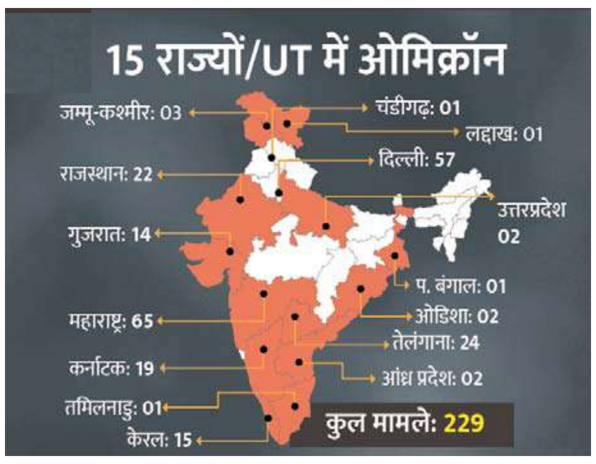

» संक्रमितों में एक विदेशी महिला भी; देश में अब 229 मामले

आईटीडीसी इंडिया ई-प्रेस/ आईटीडीसी न्यूज राजस्थान

राजस्थान में आज 4 लोगों में ओमिक्रॉन वैरिएंट की पुष्टि हुई है। जयपुर में एक व्यक्ति, उसकी पत्नी और एक बुजुर्ग की रिपोर्ट ओमिक्रॉन पॉजिटिव आई है। इसके अलावा यहां एक विदेशी महिला पॉजिटिव मिली है। महिला पिछले दिनों जांच करवाने के बाद दिल्ली चली गई थी।0 000 ़000 हेल्थ एक्सपर्ट्स ने कहा- साइंटिफिक रिसर्च के बाद बूस्टर डोज पर फैसला लेगी सरकार नीति आयोग के सदस्य डॉ. वीके पॉल ने बुधवार को कहा कि कोरोना के बढ़ते हुए मामलों में हो रहे किसी भी बदलाव को हम बहुत सावधानी से देख रहे हैं। कोरोना हमेशा शुरुआती स्टेज में हल्के लक्षणों के साथ आता है। उन्होंने कहा कि बूस्टर डोज पर कोई भी फैसला साइंटिफिक रिसर्च के बाद लिया जाएगा। हेल्थ मिनिस्टर भी संसद में यह बात दोहरा चुके हैं। वहीं AIIMS के डॉयरेक्टर डॉ. रणदीप गुलेरिया ने कहा कि ओमिक्रॉन ज्यादा संक्रामक है। अब तक मिले डेटा के मुताबिक ओमिक्रॉन में हल्की बीमारी के ही लक्षण दिख रहे हैं। इसमें गंभीर बीमारी के लक्षण अभी नहीं देखे जा रहे हैं। हमें इसके बारे में और डेटा चाहिए। जैसे-जैसे मामले बढ़ेंगे, हमें इसके लक्षणों के बारे में और जानकारी मिलेगी। वैक्सीन की डोज लगवाना और कोविड नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई हैं उन्हें जल्द ही डोज लगवा लेनी चाहिए।

प्रधानमंत्री के प्रोग्राम के बाद रो पड़ीं ड्रीम गर्लःधक्का-मुक्की से हेमा के आंसू निकले

नई दिल्ली। एक्ट्रेस और मथुरा से BJP सांसद हेमा मालिनी मंगलवार को प्रयागराज में मोदी के प्रोग्राम के बाद रो पड़ीं। परेड ग्राउंड में आयोजित मातृशक्ति कार्यक्रम से निकलते हुए हेमा भीड़ की धक्का-मुक्की में फंस गईं। इससे ड्रीम गर्ल इतनी परेशान हुईं कि उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। यह देखकर सिक्योरिटी में तैनात पुलिस अफसरों ने मोर्चा संभाला और उन्हें निकाला। इस बीच एक ड्रामा और हुआ कि हेमा मालिनी से मिलने की जिद पकड़ते हुए BJP MLC सुरेंद्र चौधरी पुलिस से भिड़ गए। दरअसल उन्हें पुलिस ने हेमा मालिनी के पास पहुंचने से रोक दिया था। इस पर चौधरी बिफर गए और बोले कि वे हीरोइन ही तो हैं, मिलने में क्या दिक्कत है? अफसरों ने उन्हें समझाया कि वे किसी को भी अंदर नहीं जाने दे सकते।

उत्तराखंड के स्कूल में छुआछूत बच्चों ने दलित महिला का बनाया खाना खाने से मना किया

नई दिल्ली। उत्तराखंड के चंपावत जिले में ऊंची जाति के छात्रों ने दलित महिला के पकाए गए भोजन को खाने से इनकार कर दिया है। इस पर राज्य में सामाजिक भेदभाव और जातिगत पूर्वाग्रह को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। अनुसूचित जाति की सुनीता देवी को हाल ही में सुखीढांग इलाके के जौल गांव के गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल में भोजनमाता के तौर पर नियुक्त किया गया। उन्हें कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के लिए मिड डे मील तैयार करने का काम सौंपा गया था। स्कूल के प्रिंसिपल प्रेम सिंह ने बताया कि सुनीता की ज्वाइनिंग के पहले दिन ऊंची जाति के स्टूडेंट्स ने भोजन किया था।

अपनी ही सरकार की घेराबंदी : केंद्रीय मंत्री कुलस्ते बोले-

सरकारी कंपनियां प्राइवेट कर दीं, अब इस सेक्टर में आरक्षण दो नहीं तो आंदोलन करेंगे

आईटीडीसी इंडिया ई-प्रेस/ आईटीडीसी न्यूज नई दिल्ली

केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने जयपुर में अपनी ही सरकार को मुश्किल में डालने वाला बयान दिया है। उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण देने की वकालत करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने की बात कही है। मंगलवार को आदिवासी विकास परिषद के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कुलस्ते ने कहा कि सरकारी कंपनियों का निजीकरण हो रहा है। ऐसे में सरकार को प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन लागू करना चाहिए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो हमें सरकार के खिलाफ प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू करने के लिए आंदोलन भी खड़ा करना पड़ेगा। कुलस्ते ने कहा कि हमें आक्रामक रुख अपनाते हुए अपने नेताओं और राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। तभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के कान खुलेंगे। आरक्षण खत्म हो गया तो हमारे लोगों को कोई लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए वक्त रहते हम सबको मिलकर आरक्षण के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। कुलस्ते ने कहा कि आदिवासी चुनाव में अपनी ताकत दिखाएं, जिससे राजनीतिक पार्टियों में संदेश जाएगा कि हमारे बिना आप की सरकार नहीं बनेगी।

दैनिक इंटीग्रेटेड ट्रेड

अर्थव्यवस्था, शिक्षा, नियोजन, उद्भव, पर्यावरण, मनोरंजन.

आपकी बात आपके साथ

जी-सोनी मर्जर को बोर्ड की मंजूरी : नई कंपनी में सोनी की 50.86 फीसदी हिस्सेदारी होगी

पुनीत गोयनका कंपनी के MD और CEO रहेंगे

आईटीडीसी इंडिया ई-प्रेस/ आईटीडीसी न्यूज नई दिल्ली

जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड के बोर्ड ने सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया के साथ मर्जर को मंजूरी दे दी है। नई कंपनी में सोनी की 50.86 फीसदी हिस्सेदारी होगी, जबकि ZEEL के प्रमोटर ग्रुप एस्सेल के पास 3.99 फीसदी हिस्सेदारी होगी। ZEEL के शेयरहोल्डर्स के पास 45.15 फीसदी स्टेक होगा। मर्ज एनटीटी की वैल्यू करीब 52100 करोड़ रुपए की होगी। मार्केट एक्सपर्ट जितनी अपेक्षा कर रहे थे ये वैल्यू उससे काफी कम है। जी के पास वर्तमान में 96.05 करोड़ शेयर हैं, मर्जर के बाद उनकी हिस्सेदारी बढ़कर 173.63 करोड़ हो जाएगी। जी के प्रमोटर्स को 1101 करोड़ रुपए की नॉन कम्पीट फी मिलेगी। ये इन पैसों को मर्जर में इंफ्यूज करेंगे। प्रमोटर 3.99 फीसदी हिस्सेदारी बनाए रखने के लिए नई कंपनी में 300 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से 3.67 करोड़ से ज्यादा शेयर खरीदेंगे। पब्लिक शेयरहोल्डर्स को नई कंपनी में "श्वश्वरु के 100 शेयरों के बदले 85 शेयर मिलेंगे। दोनों कंपनियों के बीच मर्जर का ऐलान 22 सितंबर 2021 को किया गया था। 90 दिन का ड्यू डिलिजेंस पीरियड 21 दिसंबर को खत्म हुआ है।

ZEEL को मिलेगा ग्रोथ कैपिटल

एक दूसरे के कंटेंट, डिजिटल प्लेटफॉर्म का एक्सेस

सोनी को भारत में उपस्थिति बढ़ाने का मौका मिलेगा

सोनी को 130 करोड़ लोगों की व्यूअरशिप मिलेगी

बाइंडिंग एग्रीमेंट पर साइन

दोनों कंपनियों ने बाइंडिंग एग्रीमेंट पर साइन कर दिए हैं। बाइंडिंग एग्रीमेंट का मतलब है कि अब "श्वश्वरु का मर्जर सिर्फ सोनी के साथ ही होगा। पहले 90 दिनों के लिए दोनों कंपनियों के बीच नॉन बाइडिंग एग्रीमेंट था। मतलब 90 दिनों तक दोनों पार्टियां अगर चाहती तो पीछे हट सकती थीं। लेकिन, 90 दिनों के नेगोशिएशन और बातचीत के बाद दोनों कंपनियां ने मर्जर को मंजूरी दे दी है। डील के अनुसार, सोनी 1.5 अरब डॉलर का निवेश करेगी और मर्ज की गई कंपनी में 50.86 फीसदी हिस्सेदारी रखेगी।

न्यूज ब्रीफ

उद्योग स्थापित कर रोजगार के अवसर बढ़ाएँ : डॉ. सोनवलकर

भोपाल। भारत सरकार के उपक्रम एमपीकॉन द्वारा एमपी नगर में होटल अतिशय में नव उद्यमियों के लिए उद्योग स्थापित करने के अवसर और संभावनाओं पर कार्यशाला आयोजित की गई। मुख्य अतिथि कुल सचिव, भोज मुक्त ओपन विश्वविद्यालय डॉ. जयंत सोनवलकर ने उद्योग स्थापना के इच्छुक लोगों को प्रोत्साहित करते हुए अवसरों को तलाशने के संबंध में विस्तृत मार्गदर्शन दिया। डॉ. सोनवलकर ने कहा कि अब समय नौकरी पाने का नहीं बल्कि देने का है। उद्योगों की स्थापना इस सोच को मूर्तरूप देने में बड़ा कदम साबित होगी। उन्होंने शासकीय योजनाओं की जानकारी देते हुए उनसे लाभान्वित होने की सलाह दी, जिससे उद्योग स्थापना में अधिकाधिक लोग शामिल हो सकें। कार्यशाला में भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, लघु उद्योग, उद्यमिता विकास निगम और एमपीकॉन के अधिकारियों ने भी उपस्थित नव-उद्यमियों को प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान किया।

बीएसएसएस कॉलेज के छात्र ग्रामीण क्षेत्र में मतदाताओं को बताएँगे मतदान की प्रक्रिया

भोपाल। बीएसएसएस कॉलेज भोपाल के विद्यार्थी मतदाता जागरूकता अभियान में ग्रामीण क्षेत्र में जाकर मतदाताओं को मतदान की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देंगे। त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के अंतर्गत जिला पंचायत भोपाल द्वारा मंगलवार को बीएसएसएस कॉलेज में मतदाता जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री बी.एस. जामोद ने विद्यार्थियों को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को बनाये रखते हुए मताधिकार की शपथ दिलाई। उन्होंने सेल्फी प्वाइंट एवं शुभंकर का भी विमोचन किया। भोपाल जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विकास मिश्रा ने बीएसएसएस कॉलेज के साथ एक एमओयू भी साइन किया है। इस दौरान उप सचिव राज्य निर्वाचन आयोग डॉ. सुतेश शाक्या और कॉलेज के प्राचार्य, प्रोफेसर और विद्यार्थी उपस्थित थे।

शासकीय विद्यालयों के सांस्कृतिक कार्यक्रम अनुगूँज का दो दिवसीय आयोजन

भोपाल। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों की सहभागिता से होने वाला अनुगूँज 2021-22 सांस्कृतिक कार्यक्रम का 22-23 दिसंबर को किया जा रहा है। कार्यक्रम के समापन दिवस 23 दिसंबर को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि होंगे और स्कूल शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) एवं सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री श्री इन्दर सिंह परमार अध्यक्षता करेंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ 22 दिसंबर को स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री श्री परमार के मुख्य आतिथ्य में होगा। दोनों दिवस के कार्यक्रम शाम 5 बजे से शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय, भोपाल में होंगे। इस बार अनुगूँज भारत वर्ष की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगाँठ की थीम आज़ादी का अमृत महोत्सव पर आधारित है। इसमें अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को सहेजते हुए एक फारवर्ड लुकिंग एस्पिरेशनल भारत को दर्शाने का प्रयास किया गया है। भारत सरकार की एक भारत-श्रेष्ठ भारत अवधारणा के तहत सांस्कृतिक सम्पदा के आदान-प्रदान के लिए मध्यप्रदेश राज्य को नागालैंड और मणिपुर राज्यों के साथ समूहबद्ध किया गया है। अनुगूँज की प्रस्तुतियों और परिकल्पनाओं में भारत के इन उत्तर-पूर्वी राज्यों की कला और संस्कृति की झलक भी सम्मिलित है।

अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय में 147 शैक्षणिक पदों की स्वीकृति

आईटीडीसी इंडिया ई-प्रेस/ आईटीडीसी न्यूज नई दिल्ली

अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय में 147 शैक्षणिक पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है। यह निर्णय उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित साधारण परिषद की बैठक में लिया गया। कार्यपरिषद ने यूजीसी द्वारा शैक्षणिक पदों की स्वीकृति के लिए निर्धारित मानदण्डों के अनुसार विश्वविद्यालय में 21 विषयों के लिए प्रत्येक विषय में एक प्राध्यापक, दो सह-प्राध्यापक तथा चार सहायक प्राध्यापक के आधार पर कुल 21 प्राध्यापक, 42 सह-प्राध्यापक एवं 84 सहायक प्राध्यापक के पदों की स्वीकृति दी है। साधारण परिषद ने हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए अटल शोधपीठ की स्थापना, अत्याधुनिक एवं सर्व-सुविधायुक्त लैग्वेंज लेब की स्थापना की स्वीकृति भी दी। साथ ही अटल बिहारी हिन्दी विश्वविद्यालय के नवीन अध्ययन केन्द्रों के प्रारंभ करने, विश्वविद्यालय स्तर पर अखिल भारतीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए कार्य-योजना तथा भारत सरकार की कौशल विकास योजना में निरोग केन्द्र योजना विश्वविद्यालय में प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त कार्य परिषद के लिए साधारण परिषद के दो सदस्य राकेश दांगी और आनंद कुमार सिंह को मनोनीत किया गया। प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा अनुपम राजन, अपर आयुक्त दीपक सिंह, राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति सुनील कुमार, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति के. सुरेश, भोज मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति जयंत सोनवलकर सहित अन्य सदस्य मौजूद थे।

ljksftuh uk;Mw 'kkldh; dU;k Lo'kklh egkfo|ky;] f'kokth uxj Hkksiky esa py jgs ;qok mRlo dk;Z@e ds rgr cq/kokj ds fnu okn&fookn ,oa oDr`rk izfr;ksfxrkvksa dk vk;kstu fd;k x;kA okn& fookn izfr;ksfxrk dk fo"k;/kk& fSLok/khu Hkkjr dh f'k{kk O;oLFkk lkekftd mRFkku esa lgk;d gSP ftlesa fonw"kh[kjs ,oa izKk f}osnh] izKk flag rFkk vafdrk ;kno us Øe'k% izFke] f}rh;] LFkku izkIr fd;kA fSljksftuh uk;Mw dh dforkvksa esa fopkj vkSj LoIuP fo"k; ij vk/kkfjr oDr`rk izfr;ksfxrk esa v'kjk lqYrku] eqLdku dqekjh rFkk ekuch eugj us Øe'k% izFke] f}rh;] ,oa r`rh; LFkku izkIr fd;kA

नई कमिश्नरी में उलझी न्यू ईयर सेलिब्रेशन की गाइडलाइन : क्रिसमस से ईयर एंडिंग तक होने वाले जश्न पर भीड़ को खुली छूट रहेगी या रोकटोक होगी

तय नहीं कर पा रहा पुलिस-प्रशासन

आईटीडीसी इंडिया ई-प्रेस/ आईटीडीसी न्यूज भोपाल

राजधानी भोपाल में नई कमिश्नरी में न्यू ईयर सेलिब्रेशन की गाइडलाइन उलझ गई है। क्रिसमस से ईयर एंडिग तक होने वाले जश्न पर भीड़ को खुली छूट रहेगी या रोक-टोक होगी, यह न तो पुलिस तय कर पा रही है और न ही जिला प्रशासन। धारा 144 के तहत अब तक किसी प्रकार के आदेश जारी नहीं हो सके हैं। दूसरी ओर होटल-रेस्टोरेंट, पब, क्लब या ओपन स्पेस की बुकिंग शुरू हो गई है। यदि ऐनवक्त पर गाइडलाइन जारी हुई तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी। भोपाल में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू हो चुका है और अधिकांश मामलों में धारा 144 लगाने के पॉवर पुलिस के पास पहुंच गए हैं। कुछ मामलों में कलेक्टर आदेश जारी कर सकते हैं। बावजूद अब तक न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर गाइडलाइन जारी नहीं हो पाई है, जबकि पार्टी स्पेस की बुकिंग की शुरुआत हो गई है।

सरकार हटा चुकी पाबंदियां

कोरोना से जुड़ी सारी पाबंदियां प्रदेश सरकार नवंबर में ही हटा चुकी है। अब न तो नाइट कर्फ्यू लागू है और न ही होटल-रेस्टोरेंट, क्लब, ओपन स्पेस, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल आदि जगह लोगों की संख्या को लेकर कोई पाबंदी है। इसके चलते न्यू ईयर के 15 दिन पहले ही राजधानी में पार्टी के लिए जगह की बुकिंग होने लगी है। रेस्टोरेंट संचालक रामवीर सिंह ने बताया, 31 दिसंबर की रात और 1 जनवरी के लिए रेस्टोरेंट की बुकिंग हो गई है, लेकिन पशोपेश इस बात से है कि यदि सरकार, पुलिस या प्रशासन ने कोई गाइडलाइन जारी की तो हमारा तो नुकसान होगा ही, लोगों की मुश्किलें भी बढ़ जाएंगी।

भोपाल बना कोरोना हॉट-स्पॉट

भोपाल कोरोना का हॉट-स्पॉट बन चुका है। मध्यप्रदेश में दिसंबर महीने में कुल 347 संक्रमित मिल चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव भोपाल में 137 में ही मिले हैं। वहीं, एक्टिव केस 65 है। इसलिए चिंता बढ़ना भी लाजमी है। इस कारण गाइडलाइन जारी हो सकती है, लेकिन यदि गाइडलाइन जारी होने में देरी होती है तो लोगों के जश्न में खलल पड़ जाएगा।

पिछले न्यू ईयर पर 200 लोगों की थी अनुमति

पिछले साल न्यू ईयर पर होटल, पब और ओपन स्पेस में मनाए जाने की छूट थी। ओपन स्पेस जैसे गार्डन या मैदानों में होने वाले आयोजन में एक बार में 200 से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने की मनाही थी और होटल, क्लब-पब आदि में भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही आयोजन होने के निर्देश थे।

बुकिंग कर रहे

न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर अभी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है। चूंकि, सरकार ने सभी पाबंदी की छूट दे दी है। इसलिए होटल-रेस्टोरेंट की बुकिंग की जा रही है।

तेजकृपाल सिंह पाली,
अध्यक्ष होटल एसोसिएशन भोपाल

25 या 26 दिसंबर को जारी करेंगे गाइडलाइन

फिलहाल नए साल को लेकर गाइडलाइन तैयार नहीं की गई है। 25 या 26 दिसंबर को गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी।

मकरंद देउस्कर,
पुलिस कमिश्नर

मप्र ने महिला टीचर से किया रेप

इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती, छह माह तक बनाए शारीरिक संबंध

» अब शादी से मुकरा

आईटीडीसी इंडिया ई-प्रेस/ आईटीडीसी न्यूज नई दिल्ली

भोपाल के सरकारी स्कूल की महिला टीचर ने रूङ्ग(मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव) के खिलाफ कोहेफिजा थाने में दुष्कर्म का केस दर्ज कराया है। महिला ने पुलिस को बताया कि जुलाई 2021 में इंस्ट्राग्राम के जरिए रूङ्क से उसकी दोस्ती हुई थी। 20 जुलाई को घूमने के बहाने वह अपने दोस्त के फ्लैट में लेकर गया। अकेला पाकर उसके साथ रेप किया। शादी का झांसा देकर वह छह माह तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। अब मुकर गया। आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। SI अर्सिया सिद्दकी ने बताया कि भोपाल की रहने वाली 42 साल की महिला सरकारी स्कूल में टीचर हैं। वह भोपाल में ही पदस्थ हैं। उनका पति से तलाक हो चुका है। 10 साल की बेटी है। महिला का कहना है कि जुलाई 2020 में इंस्टाग्राम के जरिए सिंधी कालोनी में रहने वाले मोहित लालचंदानी नाम के युवक से दोस्ती हुई थी। मोहित ने खुद को अविवाहित बताकर शादी करने का वादा किया।

फोन बंद कर हुआ गायब

20 जुलाई को वह टीचर को घुमाने के बहाने कहकशां अपार्टमेंट, कोहेफिजा में अपने दोस्त के फ्लैट में लेकर गया। जहां, टीचर के साथ उसने दुष्कर्म किया। इसके बाद कई बार शारीरिक संबंध बनाएं। हालही में टीचर ने जब शादी के लिए कहा तो वह मुकर गया। बोला कि उसके परिवार वाले दूसरी युवती के साथ शादी तय कर दी है। इस पर टीचर ने थाने में केस दर्ज करा दिया। टीचर ने पुलिस को बताया कि मोहित की उम्र करीब 28 साल होगी। एसआई अर्सिया ने बताया कि महिला आरोपी के बारे में अधिक नहीं जानती है। आरोपी उसे झूठ बोलकर दोस्ती की थी। वह एमआर है या नहीं इसको लेकर भी संदेह है। महिला को उसका घर तक नहीं पता है। अब वह फोन बंद कर लिया है। उसकी गिरफ्तारी के बाद ही पता चल सकेगा ।

साँची विश्वविद्यालय नित नयें आयाम स्थापित करें : मंत्री ठाकुर

आईटीडीसी इंडिया ई-प्रेस/ आईटीडीसी न्यूज भोपाल

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने कहा कि साँची विश्वविद्यालय शोध की दिशा में कार्य करें जो भारतीय संस्कृति का परचम लहराएँ। उन्होंने कहा कि यह खुशी की बात है कि विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। यह विश्वविद्यालय की ख्याति ही है कि इसमें विद्यार्थियों की संख्या 70 से 450 पहुँची है। सुश्री ठाकुर साँची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय की साधारण परिषद् की चतुर्थ बैठक की अध्यक्षता कर रही थी। बैठक में प्रमुख सचिव शिवशेखर शुक्ला भी उपस्थित थे। मंत्री सुश्री ठाकुर ने कहा कि विश्वविद्यालय नित नयें आयाम स्थापित करें। सरकार की ओर से हर जरूरी आवश्यकता को पूरा किया जाएगा। बैठक में विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् के गठन के लिये साधारण परिषद् के सदस्यों के नामांकन पर निर्णय लिया गया। सुश्री ठाकुर ने दुर्लभ 18वीं एवं 19वीं सदीं की पुस्तकों के पुन: मुद्रण के लिये समिति बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संगोष्ठी भी किया जाना प्रस्तावित हैं। विश्वविद्यालय में नये शॉर्ट टर्म एवं एक सेमेस्टर अवधि के कोर्सेस सीबीसीएस पद्धति के अंतर्गत प्रारंभ किये जाएंगे। विश्वविद्यालय को आवंटित भूमि का सौन्दर्यीकरण भी करवाया जा रहा है। विश्वविद्यालय द्वारा कई संस्थानों से एमओयू भी किया गया है, जिससे विद्यार्थियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। बैठक में महाविद्यालय के संबंध में परिषद् ने सुझाव भी दिए।

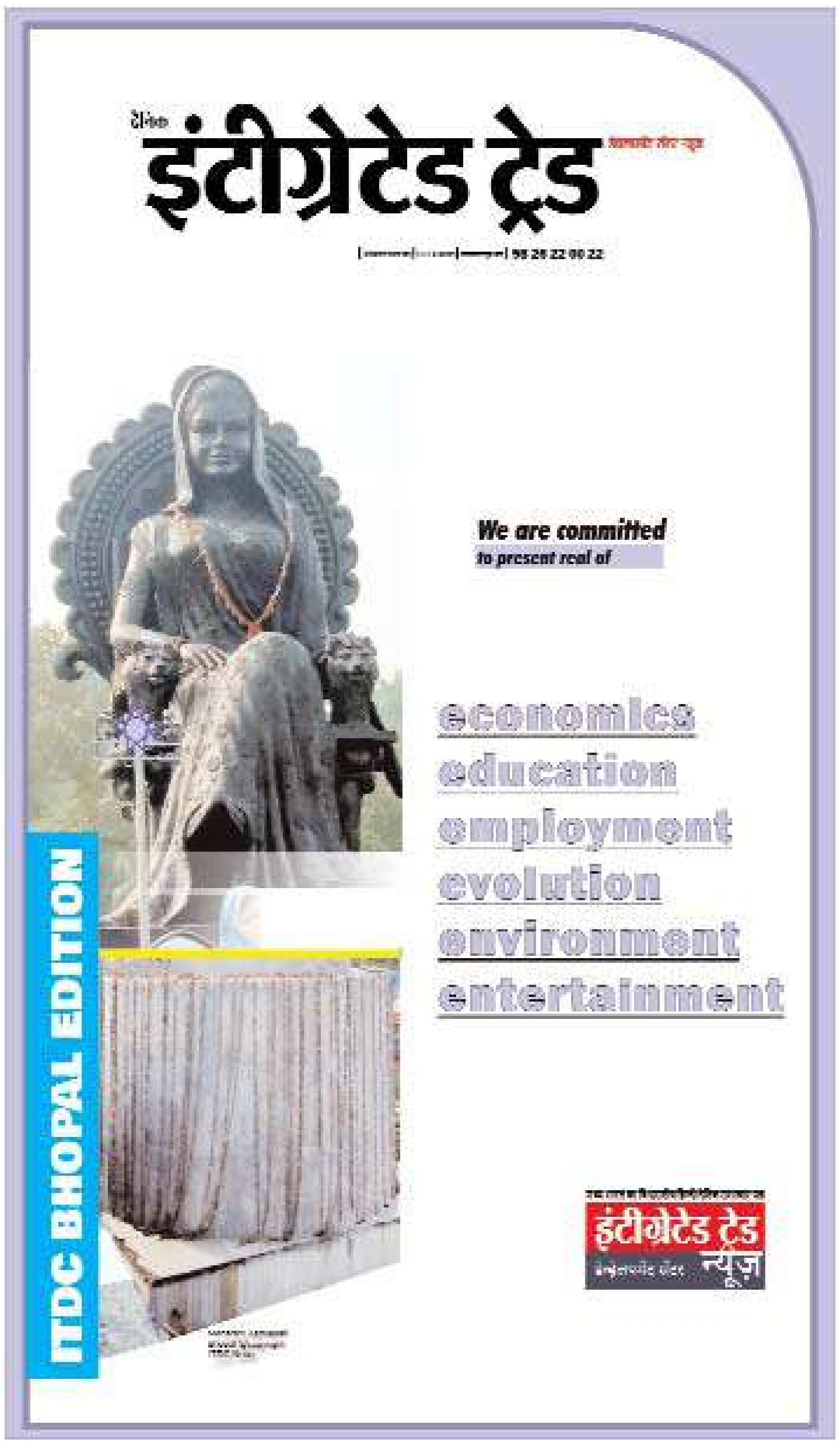

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हॉकी का प्रकाश पुस्तक का विमोचन किया।

न्यूज ब्रीफ

रिकॉर्ड स्तर पर पीई-वीसी निवेश

नई दिल्ली। वर्ष 2021 में प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल का निवेश देश में 70 अरब डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। प्राइवेट इक्विटी के निवेश रुझान का विश्लेषण करने वाली बेन ऐंड कंपनी के अनुमान से यह पता चला है। इसमें से करीब आधा निवेश केवल दो क्षेत्रों - उपभोक्ता तकनीक (ई-कॉमर्स, एडटेक, फिनटेक) और आईटी सेवाओं एवं सास (सॉफ्टवेयर सेवाएं) में हुआ है। यह दोनों क्षेत्र निवेश के लिहाज से आकर्षक कारोबार है और अगले दो से तीन साल तक इस क्षेत्र में निवेश जारी रह सकता है। बेन ऐंड कंपनी में पार्टनर, प्राइवेट इक्विटी एवं टेक्नोलॉजीज प्रैक्टिसेस, आदित्य शुक्ला ने कहा, %पिछले साल प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल का कुल निवेशक 62 अरब डॉलर रहा था। इनमें से जियो और रिलायंस रिटेल के जरिये रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अकेले सबसे ज्यादा 26.5 अरब डॉलर का निवेश जुटाया था। लेकिन इस साल कोई बड़ा सौदा नहीं हुआ। हालांकि निवेश में कुल मिलाकर तेजी देखी गई। बेन के विश्लेषण से पता चला है कि देश में 6 फंड फर्मों - ब्लैकस्टोन, कार्लाइल, जीआईसी, एडवेंट, बेरिंग और टाइगर ग्लोबल ने 2021 में कुल निवेश का करीब 20 से 25 फीसदी निवेश किया है। अन्य सकारात्मक रुझान यह रहा कि निवेश निकासी में अच्छी वृद्धि देखी गई। बेन के अनुमान के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2021 में पिछले साल के मुकाबले तीन से चार गुना ज्यादा निवेश की निकासी हुई, जो कुल करीब 8.9 अरब डॉलर रहा। इससे पहले 2018 में सबसे ज्यादा 32.9 अरब डॉलर के निवेश की निकासी हुई थी उस समय वॉलमार्ट सौदे के दौरान फ्लिपकार्ट के निवेशकों ने अपनी हिस्सेदारी बेची थी। शुक्ला ने कहा कि 2021 में कुल निकासी में से करीब एक-तिहाई उपभोक्ता तकनीक कंपनियों जोमैटो, अर्बन कंपनी और ड्रीम 11 के आईपीओ के जरिये की गई। पीई निवेश पर नजर रखने वाली फर्म वीसीएज के अनुसार 2021 में कुल निवेश सौदों की संख्या 1,914 रही जो पिछले साल के ,1416 सौदों की तुलना में 35 फीसदी अधिक है। कोविड से पहले के साल यानी 2019 में 1,564 निवेश सौदे हुए थे। कुछ प्राइवेट इक्विटी फंडों ने कई निवेश सौदे किए हैं। सिकोया कैपिटल इंडिया एडवाइजर्स ने 2021 में 123 निवेश सौदे किए, वहीं वेंचर कैपिटलिस्ट प्राइवेट लिमिटेड ने 99 सौदे और टाइगर ग्लोबल ने 95 निवेश सौदे किए। अगले साल सास क्षेत्र में पीई और वेंचर कैपिटल बड़ा दांव लगा सकते हैं। सही मायने में टाइगर ग्लोबल जैसी कंपनियां बड़ा दांव लगा रही हैं। बेन के अनुमान के अनुसार अगले दो से तीन साल में सास प्राइवेट इक्विटी के निवेश के लिहाज से प्रमुख क्षेत्र होगा। शुक्ला ने कहा, सास कंपनियों के लिए दुनिया भर में व्यापक बाजार है। ई-कॉमर्स कंपनियों से उलट ये कंपनियां अपने सकल मर्केंडाइज वैल्यू के 70 से 80 फीसदी सकल मार्जिन पर कारोबार कर रही हैं।

हिंदुस्तान यूनिलीवर ने प्रोडक्ट की बढ़ाई कीमत : रिन, लाइफबॉय, लक्स और सर्फ एक्सल हुए महंगे, 7-10 फीसदी बढ़ा दाम

आईटीडीसी इंडिया ई-प्रेस/ आईटीडीसी न्यूज नई दिल्ली

हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपने कई प्रोडक्ट की कीमतें बढ़ा दी हैं। इसमें रिन, सर्फ एक्सल, लाइफबॉय और अन्य शामिल हैं। इनके दाम में 7 से 10 फीसदी बढ़ाए गए हैं। कंपनी ने बताया कि साबुन और डिटर्जेंट दोनों की कीमतें बढ़ाई गई हैं। इसमें टिकिया और पावडर भी हैं। लाइफबॉय के मल्टीपैक की कीमत 115 से बढ़ाकर 124 रुपए कर दी गई है जबकि लक्स मल्टीपैक की कीमत 140 से 150 रुपए कर दी गई है। एक लक्स साबुन की कीमत भी इसी तरह से 28 रुपए से बढ़ाकर 30 रुपए कर दी गई है। डिटर्जेंट बार की बात करें तो सर्फ एक्सल की कीमत 108 रुपए कर दी गई है। पहले यह 98 रुपए थी। इसके सिंगल टिकिया की कीमत 16 से बढ़कर 18 रुपए हो गई है। एक महीने पहले 25 नवंबर को भी इसी तरह से चुनिंदा प्रोडक्ट की कीमतें कंपनी ने बढ़ाई थी। उस समय साबुन और डिटर्जेंट की कीमत 10 फीसदी तक बढ़ाई गई थी।

- पाम ऑइल की कीमतें अपने टॉप पर हैं
- माल-ढुलाई भी महंगी हो गई है
- साबुन के लिए लगने वाले अन्य सामान भी महंगे हुए

नवंबर में बढ़ी थीं कीमतें

नवंबर में व्हील के एक किलो के पैकेट की कीमत 3.5 फीसदी या 2 रुपए बढ़ाई गई थी। इसके आधा किलो के पैक की कीमत भी 2 रुपए बढ़ाकर 28 से 30 रुपए कर दी गई थी। रिन बार की कीमत 5.8 फीसदी बढ़ाई गई थी। लक्स के 100 ग्राम पैक की कीमत 21.7 फीसदी बढ़ाकर 25 रुपए कर दी गई थी।

रॉ मैटेरियल की कीमतें बढ़ीं

फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स (स्नस्नष्टत्र) कंपनियों को पिछले कुछ समय से महंगाई के दबाव का सामना करना पड़ रहा है। यह दबाव ईंधन की बढ़ती कीमतों, पाम तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ-साथ अन्य मूल्यवान सामानों के अलावा माल-ढुलाई की ऊंची लागत के कारण है। हाल ही में पारले प्रोडक्ट्स ने भी ज्यादा लागत को कम करने के लिए कीमतें बढ़ा दी हैं। इसने अपने बिस्कुट की सभी कैटिगरी की कीमतों को बढ़ाया है। हालांकि कुछ मामलों में इसने पैकेट का वजन कम कर दिया है।

जून में मैनेजमेंट ने दिया था कीमतों को बढ़ाने का संकेत

जून तिमाही के रिजल्ट में हिंदुस्तान यूनिलीवर के टॉप मैनेजमेंट ने कहा कि उसने स्किन की सफाई, लॉन्ड्री और चाय पोर्टफोलियो के प्रोडक्टस में दूसरी दफा कीमतें बढ़ाई हैं। कंपनी के प्रबंधन ने कहा कि बिजनेस मॉडल को बचाए रखने के लिए ये जरूरी था। फिर सितंबर तिमाही के रिजल्ट के समय कंपनी ने आगाह किया कि इनपुट लागत ज्यादा ही रहने वाली है। कंपनी के टॉप मैनेजमेंट ने तब कहा था कि कीमतें काफी सोच-विचार कर बढ़ाई गईं हैं।

भारत में एपल प्लांट 5 दिनों के लिए बंद

फूड पॉइजनिंग विवाद के बीच ठप्प रहेगा प्रोडक्शन

इससे सप्लाई पर नहीं पड़ेगा असर

आईटीडीसी इंडिया ई-प्रेस/ आईटीडीसी न्यूज नई दिल्ली

एपल सप्लायर फॉक्सकॉन फूड पॉइजनिंग की घटना के विरोध के बाद चेन्नई के पास का प्लांट इस हफ्ते बंद रहेगा। कांचीपुरम के पुलिस अधीक्षक ने कहा कि प्लांट में 5 दिनों की छुट्टी घोषित की गई है। तमिलनाडु के एक सीनियर ऑफिसर ने भी इसकी पुष्टि की। हांलाकि, फॉक्सकॉन और एपल के तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। फॉक्सकॉन प्लांट में पिछले हफ्ते फूड पॉइजनिंग की घटना के बाद 150 कर्मचारियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। फॉक्सकॉन वही फैक्टरी है जहां आईफोन 12 मॉडल बनाया जाता है। एपल ने हाल ही में कारखाने में अपने प्रमुख आईफोन 13 के भी प्रोडक्शन की टेस्टिंग शुरू की थी। कंपनी के फरवरी तक डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों के लिए भारत में इस मॉडल का कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू करने की उम्मीद है।

फॉक्सकॉन में आईफोन 12 का होता है प्रोडक्शन

- इसमें आईफोन 13 के प्रोडक्शन की टेस्टिंग भी शुरू हुई
- फैक्ट्री में अमेजन फायर TV स्टिक और शाओमी के डिवाइस भी बन रहे

5 दिन प्लांट बंद रहने से सप्लाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा

मार्केट रिसर्च फर्म ङ्कष्टष्ट के डायरेक्टर नवकेन्द्र सिंह के मुताबिक ये समय अभी मंदी का चल रहा है जो कम से कम फरवरी तक रहेगा, इसलिए बंद का असर नहीं दिखेगा। वहीं 2022 की पहली तिमाही में नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग के बाद सेल्स में ग्रोथ होगी, तब जाकर सप्लाई की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। इसी फैक्ट्री में अमेजन फायर ञ्जङ्क स्टिक और कुछ शाओमी के डिवाइस भी बनते हैं।

एक साल में भारत का यह दूसरा मामला

फॉक्सकॉन में एक साल में भारत का यह दूसरा मामला जब कंपनी का काम रुका है। दिसंबर 2020 में विस्ट्रॉन कॉर्पोरेशन ने एक फैक्ट्री में हजारों ठेका श्रमिकों ने कथित रूप से मजदूरी का भुगतान न करने पर उपकरण और व्हीकल्स को नष्ट कर दिया था, जिससे 60 मिलियन(करीब 455 करोड़) का नुकसान हुआ था। एपल भारत में अपने आईपैड टैबलेट की असेंबली लाने की भी योजना बना रहा है। भारत मैक्सिको और वियतनाम जैसे देशों में से है, जो अमेरिकी ब्रांड्स की सप्लाई करने वाले कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर के लिए जरूरी बन रहे हैं। इसके साथ ही चीन-अमेरिका के बढ़ते तनाव के बीच भारत चीन पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहा है।

आईआईटीः वेतन में औसतन 20 फीसदी की तेजी

आईटीडीसी इंडिया ई-प्रेस/ आईटीडीसी न्यूज नई दिल्ली

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) के प्लेसमेंट के पहले चरण में अब तक के औसत वेतन में पिछले साल की तुलना में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कुछ कैंपस में पेशकश की गई नौकरियों की संख्या 45 प्रतिशत से बढ़कर 100 प्रतिशत से अधिक हो गई है। आईआईटी दिल्ली में वेतन के लिहाज से गुणवत्ता वाली नौकरियों में सुधार हुआ है। संस्थान ने कहा, %नियोक्ताओं से मिले संकेतों के मुताबिक इस साल कैंपस में दिए गए औसत वेतन में 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। इस बीच, आईआईटी पटना में घरेलू कंपनियों की तरफ से पैकेज में सबसे ज्यादा 30 फीसदी की बढ़ोतरी देखी गई जो पिछले साल के 47 लाख रुपये सालाना से बढ़कर इस साल तक 61.3 लाख रुपये सालाना हो गया। वहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर के सबसे ज्यादा पैकेज के लिहाज से देखा जाए तो एक्सेंचर जापान की ओर से सबसे ज्यादा 47.9 लाख रुपये सालाना की पेशकश की गई। हालांकि अधिकांश कैंपस में अभी प्लेसमेंट का पहला चरण भी होना बाकी है जो 1 दिसंबर से शुरू होगा। कुछ पुराने आईआईटी संस्थानों में वेतन पैकेज में काफी तेजी देखी गई है और खासतौर पर कंपनियों द्वारा पहले दिन उम्मीदवारों को बड़ी पेशकश की गई। उदाहरण के तौर पर आईआईटी रुड़की में फाइनल प्लेसमेंट प्रक्रिया के पहले सत्र के पहले ही दिन सबसे अधिक 2.15 करोड़ रुपये के अंतरराष्ट्रीय स्तर के पैकेज की पेशकश की गई जो अब तक का उच्चतम प्रस्ताव है। उबर ने पहले ही दिन आईआईटी गुवाहाटी और आईआईटी बंबई में 2.05 करोड़ रुपये के सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीटीसी (कॉस्ट-टू-कंपनी) की पेशकश की थी।

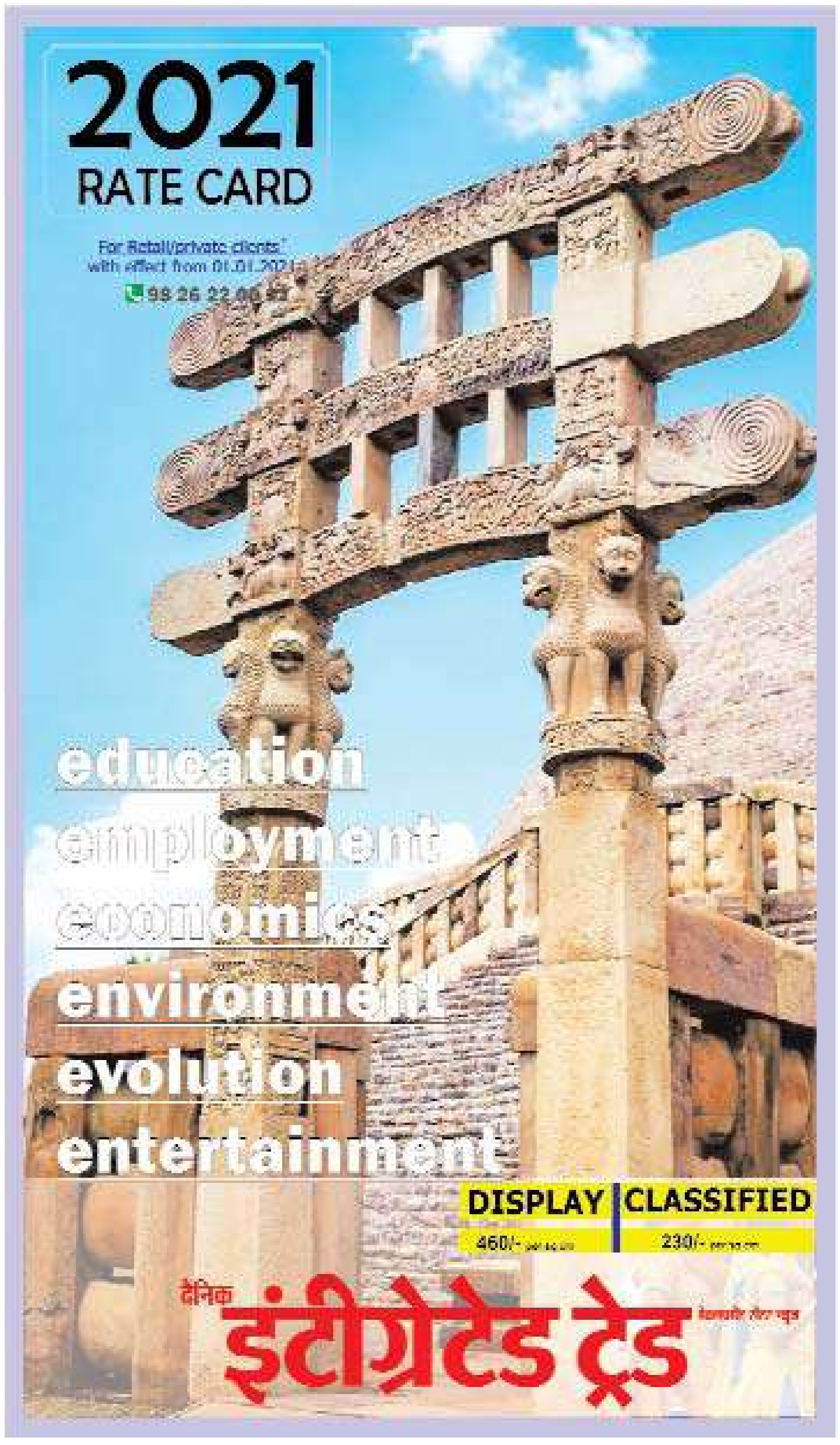

टैक्स टॉकसीनियर सिटीजंस को 3 लाख तक की आय पर नहीं देना होता टैक्स, इन्हें मिलती हैं कई तरह की इनकम टैक्स छूट

आईटीडीसी इंडिया ई-प्रेस/ आईटीडीसी न्यूज नई दिल्ली

वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 31 दिसंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। ऐसा न करने पर आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है तो आपको न सिर्फ ज्यादा टैक्स छूट का लाभ मिलता है बल्कि निवेश और रिटर्न पर भी इनकम टैक्स से खास रियायतें मिलती हैं। हम आपको इनकम टैक्स रिटर्न पर सीनियर सिटीजंस को मिलने वाले खास फायदों के बारे में बता रहे हैं।

3 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं

सीनियर सिटीजंस के लिए एक वित्तीय वर्ष में टैक्स छूट की सीमा 3 लाख रुपए है, वहीं एक आम आदमी को केवल 2.5 लाख रुपए तक ही टैक्स छूट मिलती है। 80 साल से ज्यादा उम्र (अति वरिष्ठ नागरिकों) के लिए यह 5 लाख रुपए है। यानी अगर किसी सीनियर सिटीजन की सालाना आय 3 लाख रुपए तक है और ञ्जष्ठस् की कटौती नहीं की गई है, तो उसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह अति वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए तक सालाना इनकम न होने पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है।

- इलाज पर होने वाले खर्च पर भी टैक्स छूट मिलती है
- सेविंग्स अकाउंट और FD से मिले 50 हजार तक के ब्याज पर टैक्स छूट मिलती है

ब्याज से होने वाली कमाई पर डिडक्शन

वरिष्ठ नागरिक सेविंग्स बैंक अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट से मिले ब्याज पर 50 हजार रुपए (सालाना) तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। आम लोगों के लिए यह सीमा 10 हजार रुपए तय की गई है। इंश्योरेंस प्रीमियम के भुगतान पर डिडक्शन इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80D के तहत सीनियर सिटीजन द्वारा भुगतान किए गए 50 हजार रुपए तक के मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम को डिडक्शन के तौर पर मंजूरी है। दूसरे नागरिकों के लिए यह सीमा 25 हजार रुपए है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80DDB के तहत सीनियर सिटीजन टैक्सपेयर कुछ स्पेसिफिक बीमारियों के इलाज पर हुए खर्च के लिए 1 लाख रुपए तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। 60 साल तक की उम्र का व्यक्ति इस पर 40 हजार रुपए तक का डिडक्शन ही ले सकता है। 75 साल से ज्यादा उम्र वालों को टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होती। 75 साल से अधिक की उम्र के ऐसे लोगों को ITR भरने की जरूरत नहीं होती है, जो सिर्फ पेंशन या बैंक के ब्याज से होने वाली आय पर निर्भर हैं।

शादी के लिए कानूनी उम्र सीमा 21 वर्ष

सही माहौल हो तो कानून की क्या जरूरत

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में लड़कियों की शादी की कानून उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने की मंजूरी दी है। हालांकि इसके पीछे मुख्य कारण कम उम्र में होने वाली शादियों को रोकना है, फिर भी इसकी गहराई में जाएं तो कई बातें सामने आती हैं, जिन पर ध्यान देना जरूरी है। आंकड़ों की बात करें, तो नैशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-5 से यह बात निकली है कि 23 प्रतिशत महिलाओं की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में होती है। देश में यह प्रयास चल रहा है कि 18 वर्ष से कम उम्र में लड़कियों की शादी न हो। अब हालात बदल गए हैं और 56 प्रतिशत लड़कियों की शादी 21 वर्ष से कम उम्र में होने लगी है। अगर कानून आ जाता है तो 21 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों की शादियां गैरकानूनी हो जाएंगी। इसका मतलब यह हो जाता है कि आज के समय में जितनी शादियां हो रही हैं, उसकी आधी शादियां गैरकानूनी की श्रेणी में आ जाएंगी। इस कानून को कैसे लागू किया जाए, यह ठीक से समझने की जरूरत है। पहली बात, कम उम्र की शादियों का मामला अब घटता जा रहा है। 15-20 सालों से देखा जा रहा है कि लड़कियों की शादी की औसत उम्र बढ़ रही है। इसके अलग-अलग कारण हैं। विस्तार में न भी जाएं तो इतना जरूर कहा जा सकता है कि सिर्फ कानून पारित होने से शादी की उम्र नहीं बढ़ेगी। उसके लिए और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। यह भी कि लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 वर्ष करने का बहुत कुछ लॉजिक नहीं है। 18 से कम उम्र में वे बच्चे होते हैं और बच्चों का अपना हक होता है। यह माना जाता है कि 18 साल तक लोग अपने-आप निर्णय नहीं ले सकते हैं क्योंकि उनकी इमोशनल, मेंटल, फिजिकल मच्योरिटी अभी आई नहीं होती है। लेकिन 18 साल के बाद जब हम कहते हैं कि वे सरकार चुन सकती हैं या कोई और भी निर्णय ले सकती हैं, तो शादी क्यों नहीं कर सकतीं चाइल्ड मैरिज कानून का ज्यादातर इस्तेमाल कौन करता है यदि इस मसले को हम देखें तो माता-पिता और समुदाय इसका इस्तेमाल तब करते हैं, जब लड़की अपने मन से शादी करना चाहती है। माता-पिता जब उस शादी को पसंद नहीं करते हैं, तब लड़कियां घरों से भाग जाती हैं और चॉइस मैरिज करना चाहती हैं। ऐसे में लड़की के माता-पिता उस कानून का इस्तेमाल करना चाहते हैं, ताकि लड़की अपनी मर्जी से शादी न करे और उसे घर वापस लाया जा सके। अब तक जो कानून चला है, वह लड़कियों की तरफ से नहीं चला है, बल्कि उनके खिलाफ चला है। यह भी सोचने की जरूरत है कि कम उम्र में होने वाली शादियां रोकने के लिए कानून बनाने के साथ-साथ और क्या स्टेप्स लेने चाहिए। हम फिर से अपने अनुभवों से देखें कि बाल विवाह क्यों होता है, किन परिवारों में होता है तो स्पष्ट होता है कि ज्यादातर गरीब और कम पढ़े-लिखे परिवारों में ऐसा होता है। ये परिवार क्यों ऐसा फैसला करते हैं इसका एक बड़ा कारण यह भी सामने आता है कि माता-पिता को अपनी बेटी की सेफ्टी की बहुत चिंता होती है। उन्हें लगता है कि जब लड़की मच्योर हो जाए तो ज्यादा समय उसे घरों में रखेंगे तो पता नहीं उसे सुरक्षित रख पाएंगे या नहीं। समाज क्या कहेगा स्पष्ट है कि कानून से ज्यादा जरूरी है ऐसा माहौल बनाना, जिससे यह डर नहीं रहे। उन्हें समझाना होगा कि लड़कियां पढ़ाई करना चाहती हैं, नौकरी करना चाहती हैं, तो उन्हें ऐसा करने देने में कोई हर्ज नहीं है।

15-20 सालों से देखा जा रहा है कि लड़कियों की शादी की औसत उम्र बढ़ रही है। इसके अलग-अलग कारण हैं। विस्तार में न भी जाएं तो इतना जरूर कहा जा सकता है कि सिर्फ कानून पारित होने से शादी की उम्र नहीं बढ़ेगी। उसके लिए और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। यह भी कि लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 वर्ष करने का बहुत कुछ लॉजिक नहीं है।

संपादकीय

केरल में हत्या की राजनीति

पिनराई विजयन के नेतृत्व वाले लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) ने अपना काम शुरू कर दिया है। हिंसा पर सख्ती से रोक लगाने के मुख्यमंत्री के आह्वान से अच्छी शुरुआत हुई है। यह सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि राज्य में सांप्रदायिक ताकतों का वर्चस्व न हो। यह देखने के लिए कि राज्य शांति और सांप्रदायिक सद्भाव का क्षेत्र बना रहे, राजनीतिक स्पेक्ट्रम के सभी दलों को एक बड़ी भूमिका निभानी है। साम्प्रदायिक सौहार्द्र खतरे में है। इसे राज्य के आदेश पर पूरी ताकत से बचाव करना होगा। यही समय की मांग है। केरल में हत्या की राजनीति की पुनरावृति हो रही है। 12 घंटे में दो हत्याएं हुई हैं। इस घटना ने राज्य को करारा झटका दिया है। दोनों हत्याएं अलाप्पुझा जिले में हुईं हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) के राज्य सचिव के एस शान की शनिवार रात एक गिरोह ने हत्या कर दी थी, वहीं बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के राज्य सचिव रंजीत निवासन की उनके घर पर उनकी मां के सामने हत्या कर दी गई। जिला पुलिस का कहना है कि हत्याएं एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं। यह दर्शाता है कि यह जवाबी कार्रवाई हो सकती है। पुलिस एसडीपीआई और आरएसएस कार्यकर्ताओं सहित 50 लोगों को पहले ही हिरासत में ले चुकी है। दोहरे हत्याकांड से उत्पन्न अस्थिर स्थिति को देखते हुए निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। एक के बाद एक हुई राजनीतिक हत्याओं ने पुलिस को राज्य भर में सुरक्षा कड़ी करने के लिए मजबूर कर दिया है। 534 पुलिस थानों में से 140 थानों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जहां सांप्रदायिक और राजनीतिक हिंसा की घटनाएं हुई हैं। हिंसा में नवीनतम वृद्धि का निकटतम कारण आरएसएस के संदिग्ध कार्यकर्ताओं द्वारा एसडीपीआई के राज्य सचिव के एस शान की हत्या है। घटना के तुरंत बाद, भाजपा के ओबीसी राज्य मोर्चा के सचिव रंजीत निवासन की संदिग्ध एसडीपीआई कार्यकर्ताओं ने हत्या कर दी। उल्लेखनीय है कि अलाप्पुझा जिला वर्षों से राजनीतिक हिंसा से मुक्त रहा है। इसलिए दोहरे हत्याकांड ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। एसडीपीआई और आरएसएस दोनों का जिले में प्रभाव क्षेत्र है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस साल फरवरी में इलाके में एक आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या से हिंसा की शुरुआत हुई थी। एसडीपीआई और आरएसएस के बीच समय-समय पर जिले के वायलार, मन्नानचेरी, कायमकुलम और चारमुद जैसे इलाकों में झड़पें होती रही हैं। हिंसा में अचानक आई तेजी को एसडीपीआई और पीएफआई जैसी कट्टरपंथी ताकतों के प्रभाव में वृद्धि के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। अब तक राजनीतिक हिंसा केवल कन्नूर जिले तक ही सीमित रही है। आश्चर्य की बात यह है कि कन्नूर अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण रहा है, लेकिन अलाप्पुझा जिले में हिंसा भड़क उठी है। एलडीएफ सरकार के लिए इससे बुरे समय में हिंसा नहीं आ सकती थी। सरकार और माकपा कासरगोड जिले में पेरिया हत्याकांड के सिलसिले में पार्टी के एक पूर्व विधायक की गिरफ्तारी के प्रभाव को खत्म करने के लिए संघर्ष कर रही है। लेकिन मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने पुलिस को सख्त कार्रवाई का आदेश देकर सही काम किया है। और यह खुशी की बात है कि पुलिस पहले ही हरकत में आ गई है। जबकि केरल में राजनीतिक हिंसा कोई नई बात नहीं है, जो गंभीर चिंता का कारण है, वह है कट्टरपंथी ताकतों की बढ़ती प्रवृत्ति जैसे कि पलक झपकते हिंसा करना। यह बेहद चिंताजनक है कि एसडीपीआई और पीएफआई जैसे संगठन जवाबी हत्याओं की आरएसएस शैली का अनुकरण कर रहे हैं। यदि राज्य को और अधिक राजनीतिक हत्याओं से बचना है तो यह एक खतरनाक प्रवृत्ति है जिसे शुरू में ही समाप्त करने की आवश्यकता है। सच ही कहा जाता है कि अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता और बहुसंख्यक सांप्रदायिकता दोनों एक दूसरे का पोषण करते हैं। एक समान रूप से परेशान करने वाली प्रवृत्ति इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) जैसे राजनीतिक दलों द्वारा हिंसा के लिए खुले तौर पर उकसाने की प्रवृत्ति है। वक्फ बोर्ड की नियुक्तियों को लोक सेवा आयोग को सौंपने के कदम के विरोध में कोझिकोड में हाल ही में लीग की रैली में धार्मिक भावनाओं को भड़काने और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भड़काऊ भाषण किए गए। इसने आईयूएमएल पर एसडीपीआई, जमात और पीएफआई जैसी चरमपंथी ताकतों की कड़ी पकड़ को उजागर किया। खुद को बचाए रखने के लिए, आईयूएमएल ने इन कट्टरपंथी ताकतों की भाषा बोलना शुरू कर दिया है, जो सांप्रदायिक सौहार्द्र के ताने-बाने को प्रभावित कर सकती हैं, जिसके लिए राज्य जाना जाता है। पिनराई विजयन के नेतृत्व वाले लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) ने अपना काम शुरू कर दिया है। हिंसा पर सख्ती से रोक लगाने के मुख्यमंत्री के आह्वान से अच्छी शुरुआत हुई है। यह सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि राज्य में सांप्रदायिक ताकतों का वर्चस्व न हो। यह देखने के लिए कि राज्य शांति और सांप्रदायिक सद्भाव का क्षेत्र बना रहे, राजनीतिक स्पेक्ट्रम के सभी दलों को एक बड़ी भूमिका निभानी है। साम्प्रदायिक सौहार्द्र खतरे में है। इसे राज्य के आदेश पर पूरी ताकत से बचाव करना होगा। यही समय की मांग है।

जम्मू-कश्मीर परिसीमन पर सवाल

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 और अनुच्छेद-35 ए की वापसी के साथ ही राज्य को दो हिस्सों में बांटने का फैसला 5 अगस्त, 2019 को मोदी सरकार ने लिया था। दावा था कि इससे राज्य में विकास के नए द्वार खुलेंगे, कश्मीरी पंडितों की घर वापसी होगी, आतंकवाद पर रोक लगेगी। लेकिन लगभग ढाई साल बाद भी इस अनूठे प्रदेश में हालात सामान्य नहीं हुए हैं। लद्दाख तो अलग हो ही गया, वहां की अपनी चिंताएं हैं। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर में भी जनजीवन सामान्य नहीं हो पाया है। न आतंकवाद को खत्म किया जा सका, न कश्मीरी पंडितों की घर वापसी हुई और अब तो इस राज्य में पिछले दरवाजे से आकर विभाजनकारी खेल खेलने की कोशिश हो रही है। भाजपा परिसीमन के बहाने जम्मू-कश्मीर में अपना राजनैतिक एजेंडा यानी हिंदू बहुल वोटों को अपने पक्ष में करने के पैंतरे चल रही है, ऐसा आरोप विभिन्न राजनैतिक दल लगा रहे हैं।

दरअसल इस सोमवार दिल्ली में परिसीमन आयोग की बैठक हुई। बैठक में जम्मू क्षेत्र में छह नई सीटें और कश्मीर घाटी के लिए एक नई सीट जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव के मुताबिक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कम से कम 16 सीटें आरक्षित रहेंगी। इस प्रस्ताव के अमल में आने के बाद 83 सीटों वाली जम्मू-कश्मीर विधानसभा में जम्मू क्षेत्र की सीटें 37 से बढ़कर 43 और कश्मीर घाटी की सीटें 46 से बढ़कर 47 हो जाएंगी। अनुसूचित जाति और जनजाति मुख्य रूप से जम्मू में हैं और इसका मतलब यह हुआ कि जम्मू को लगभग 60 सीटें मिलेंगी। इसके पूर्व जम्मू-कश्मीर विधानसभा में कुल 87 सीटें थीं जिनमें लद्दाख़ की चार सीटें शामिल थीं लेकिन अगस्त 2019 के पुनर्गठन विधेयक के बाद लद्दाख़ को अलग कर दिया गया था। गौरतलब है कि भारत में परिसीमन आयोग का गठन पहली बार 1952 में किया गया। यह आजादी के बाद का दौर था, कई भारतीय रियासतें खत्म हुई थीं और एक नए लोकतंत्र का भारत में उदय हुआ था। जिसमें सरकार के सामने यह चुनौती थी कि सभी जाति, धर्म, वर्ग और समुदायों की एक समान भागीदारी लोकतंत्र में रहे। अलग-अलग भौगोलिक इलाकों में रहने वाले नागरिकों को निर्वाचन की प्रक्रिया में बराबरी का हक मिले और उन्हें उचित प्रतिनिधित्व मिले, इस लिहाज से भी परिसीमन का खास महत्व है। इसलिए 1952 के बाद 1963, 1972 और फिर 2002 में परिसीमन आयोग बने। संविधान के अनुच्छेद-81 के अनुसार, लोकसभा के संयोजन में आबादी में होने वाले बदलाव नजर आने चाहिए। हालांकि 1976 में जो परिसीमन किया गया था, उसका आधार 1971 की जनगणना थी, और उस समय सीटों की संख्या कमोबेश पहले जैसी ही थी।

राज्य की सीटों की संख्या और आबादी का अनुपात सभी राज्यों में लगभग एक सा होना चाहिए। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो कि हर राज्य को एक बराबर प्रतिनिधित्व मिले। और 60 लाख से कम आबादी वाले छोटे राज्यों को इस नियम से छूट दी जाती है। हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को कम से कम एक सीट आबंटित है, भले ही उसकी जनसंख्या कितनी भी हो। उदाहरण के लिए लक्षद्वीप की आबादी एक लाख से कम है लेकिन संसद में वहां से एक लोकसभा सांसद है। दक्षिण के राज्यों में आबादी नियंत्रित है, लेकिन ये सुनिश्चित करने के लिए कि उन्हें कम सीटें न मिलें, 2001 तक वहां परिसीमन का काम इस आधार पर रोक दिया गया कि देश में 2026 तक आबादी की एक समान वृद्धि दर हासिल कर ली जाएगी।

लेकिन पिछले साल केंद्र सरकार ने खास जम्मू-कश्मीर के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया और उसके बाद आयोग ने जम्मू और कश्मीर के तमाम राजनीतिक दलों के साथ बैठकें कीं। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने इस पूरी प्रक्रिया पर ही संदेह जताया था और इन बैठकों में भाजपा सरकार के अनुच्छेद-370 को रद्द करने का मुद्दा उठाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाया था कि जब देश में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन को साल 2026 तक के लिए रोक दिया गया तो जम्मू और कश्मीर में अभी ऐसा क्यों हो रहा है। वहीं पीडीपी ने तो परिसीमन आयोग के साथ बैठक में हिस्सा नहीं लिया था। महबूबा मुफ्ती का तर्क था कि केंद्र सरकार ने आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कोई क़दम नहीं उठाया है। उन्होंने परिसीमन की प्रक्रिया के नतीजों को %व्यापक तौर% पर पहले से तय बताया था। परिसीमन से ऐतराज जताने वाले राजनीतिक दलों ने आशंका जताते हुए कहा है कि यह परिसीमन आयोग जम्मू-कश्मीर के मुस्लिम बहुमत के ख़िलाफ़ काम करेगा और उन्हें राजनीतिक तौर पर अल्पसंख्यक में बदल देगा। पिछले साल पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा की अध्यक्षता में दिल्ली स्थित ग्रुप ऑफ़ कन्सर्न्ड सिटिज़न्स ने परिसीमन आयोग को एक ज्ञापन सौंपा था।

दक्षिण के राज्यों में आबादी नियंत्रित है, लेकिन ये सुनिश्चित करने के लिए कि उन्हें कम सीटें न मिलें, 2001 तक वहां परिसीमन का काम इस आधार पर रोक दिया गया कि देश में 2026 तक आबादी की एक समान वृद्धि दर हासिल कर ली जाएगी।

शिक्षा सुधार है रोजगार की कुंजी

केद्र सरकार का कहना है 2018 में प्रॉविडेंट फंड की सदस्यता लेने वाले श्रमिकों में 70 लाख की वृद्धि हुई है। लेकिन प्रॉविडेंट फंड की सदस्यता में वृद्धि और रोजगार में वृद्धि दो अलग-अलग बाते हैं। 2018 का समय नोटबंदी और जीएसटी का था। इन नीतियों के कारण छोटे उद्योग कम हुए थे और बड़े उद्योग बढ़े थे। छोटे उद्योग ही ज्यादा रोजगार बनाते थे। इसलिए यदि छोटे उद्योगों में 100 कर्मी बेरोजगार हुए तो हम मान सकते हैं कि बड़े उद्योगों में 50 रोजगार बने होंगे। कुछ रोजगार में 50 की गिरावट आई। लेकिन जिन 50 को रोजगार मिला वे प्रॉविडेंट फण्ड के सदस्य बने चूंकि वे बड़े उद्योगों में कार्यरत थे इसलिए प्रॉविडेंट फण्ड की सदस्यता में 50 सदस्यों की वृद्धि हुई जबकि साथ-साथ कुल रोजगार में 50 श्रमिकों की गिरावट आई। इसीलिए केंद्र सरकार द्वारा की गई सामयिक श्रम सर्वे में कहा गया कि 2012 एवं 2018 के बीच अपने देश में शहरी बेरोजगारी में तीन गुना वृद्धि हुई है। और गम्भीर विषय यह है कि यदि मान भी लें कि 2018 में 70 लाख नये रोजगार बने तो भी बेरोजगारी की समस्या का निदान नहीं होता है क्योंकि अपने देश में हर वर्ष 120 लाख नये युवा श्रम बाजार में प्रवेश कर रहे हैं। इनमें से यदि 70 लाख को रोजगार मिल भी गए तो भी 50 लाख युवा बेरोजगार ही रह जायेंगे। समस्या के गंभीर होने के दूसरे संकेत उपलब्ध हैं। केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई उपरोक्त सामयिक श्रम सर्वे के अनुसार 2012 से 2018 के बीच शहरी बेरोजगारी की दर में 3 गुना वृद्धि हुई है। इसी सर्वे के अनुसार 2018 में अपने देश में 15 से 24 वर्ष के लोगों में 28.5 प्रतिशत बेरोजगार थे जो कि विश्व की प्रमुख अर्थ व्यवस्थाओं में अधिकतम था। इसी सर्वे के अनुसार 2012 से 2018 के बीच वेतन में भी गिरावट आई है। जैसे मान लीजिये आपका 2012 में वेतन 100 रुपये प्रति दिन था। वृद्धि हुई और 2018 में आपका वेतन 110 रुपये प्रतिदिन हो गया। वेतन में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई। लेकिन मान लीजिये इसी अवधि में जो टॉफी 2012 में 1 रुपये में मिलती थी वह 2018 में 1.50 रुपये में मिलने लगी। ऐसा हुआ तो आपके वास्तविक वेतन में कटौती हुई। 2012 में आप एक दिन के वेतन में 100 टॉफी खरीद सकते थे। 2018 में एक दिन के वेतन में आपको केवल 55 टॉफी मिलेंगी चूंकि वेतन में वृद्धि कम और टॉफ़ी के दाम में वृद्धि ज्यादा हुई है। इसलिए केंद्र सरकार द्वारा की गई सर्वे में कहा गया कि 2012से 2018 के बीच वास्तविक वेतन में 1.7 प्रतिशत की गिरावट आई है। अतः बेरोजगारी की समस्या को झुठलाने से काम नहीं चलेगा। इसके मूल कारणों का निवारण करना होगा। बेरोजगारी की समस्या का प्रमुख कारण तकनीकी बदलाव है। जैसे पूर्व में बैंक में खाते क्लर्कों द्वारा रखे जाते थे। अब यह कार्य कम्प्यूटर से होने लगा है। बैंक की कई शाखाओं में केवल दो या तीन कर्मी काम करते हैं। कम्प्यूटर ने श्रमिकों की जरूरत को कम कर दिया है। लेकिन साथ-साथ बैंकों का प्रसार बढ़ा है और शाखाओं की संख्या बढ़ी है। इनमें नये रोजगार उत्पन्न हुए हैं। इतिहास पर गौर करें तो किसी समय यातायात का प्रमुख साधन घोड़ा गाड़ी हुआ करती थी। इसके बाद कार का आविष्कार हुआ जिसके कारण घोड़ा गाड़ी चलाने वाले बेरोजगार हो गये। लेकिन कार के चलन का विस्तार हुआ इनके उत्पादन और मरम्मत में नये रोजगार बने। इनके लिए सड़क और फ्लाईओवर बनाने में भी रोजगार बने। इसलिए घोड़ा गाड़ी में रोजगार में गिरावट के बावजूद यातायात क्षेत्र में कुल रोजगार बढ़े। वर्तमान समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खतरा हमारे सामने है। तमाम कार्य जैसे हड्डी में फ्रैक्चर को पहचानना अथवा खून के रुग की जांच करना अब कम्प्यूटर द्वारा किये जाने लगे हैं। ऐसा होने से रेडियोलाजिस्ट और पैथोलाजिस्ट के रोजगार पर संकट आने को है। लेकिन जिस प्रकार घोड़ा गाड़ी के समाप्त होने के बावजूद कार के चलन से कुल रोजगार में वृद्धि हुई; उसी प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस से तमाम नये उत्पाद बन सकते हैं जैसे आपके मनपसन्द प्लाट का सिनेमा बनाना अथवा वीडियो मिक्स करना इत्यादि। अतः हमें अपने युवाओं को रोजगारों की इन नई संभावनाओं को पकड़ने को प्रशिक्षित करना होगा। यहां प्रमुख समस्या हमारी शिक्षा व्यवस्था की है। वर्तमान में युवाओं का रुझान सरकारी नौकरियों की तरफ बना हुआ है, बावजूद इसके कि सरकारी नौकरियों की संख्या में कमी आई है। लेकिन सामान्य शिक्षा वाले प्राइमरी सरकारी स्कूल के टीचर को आज 50 से 70 हजार रुपये प्रति माह मिलता है जबकि एक ट्रेंड नर्स अथवा डाटा इंट्री आपरेटर को बमुश्किल 15 हजार रुपये प्रतिमाह मिलता है। इसलिए युवाओं को नर्स अथवा डाटा इंट्री आपरेटर की क्षमता हासिल करने में रुचि नहीं है। उनका पूरा ध्यान सरकारी नौकरी हासिल करने की तरफ मात्र रहता है। वास्तविक %शिक्षा% ग्रहण करने में उनकी रुचि नहीं है। सरकार को चाहिए कि सरकारी कर्मियों और साधारण नागरिकों जैसे नर्स के वेतन के बीच संतुलन स्थापित करे जिससे सरकारी नौकरी का मोह कम हो और हमारे युवा सच्ची पढ़ाई पर ध्यान दें। इस दिशा में सरकार को प्राइमरी स्तर पर ही अंग्रेजी भाषा और कम्प्यूटर शिक्षा को अनिवार्य कर देना चाहिए जिससे कि युवा आने वाले समय में कम्प्यूटर आधारित रोजगार जैसे पुस्तकों का अनुवाद करना अथवा वीडियो मिक्स करना जैसे कार्यों को स्वयं कर सकें और अपनी जीविका अर्जित कर सकें। हमें इस चिंता में नहीं रहना चाहिए कि अंग्रेजी को अपनाने से हमारी संस्कृति की हानि होगी। हमें ध्यान करना चाहिए कि किसी समय हमारी संस्कृति सिन्धु घाटी की भाषा में समझी जाती थी। इसके बाद वही प्राकृत भाषा में परिवर्तित हुई और फिर देवनागरी में। लेकिन संस्कृति की निरन्तरता कायम रही। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि अपनी संस्कृति का अंग्रेजीकरण करें जिससे कि हम अंग्रेजी भाषा में उत्पन्न होने वाले रोजगार भी हासिल करें और साथ-साथ अपनी संस्कृति का वैश्वीकरण भी कर सकें। यदि हम अपने वेद, पुराण तथा करपात्रीजी महाराज जैसे विद्वानों की टीकों को सुलभ अंग्रेजी में उपलब्ध करा दें तो हमारी संस्कृति का भी वैश्वीकरण होगा और युवाओं को

इन नीतियों के कारण छोटे उद्योग कम हुए थे और बड़े उद्योग बढ़े थे। छोटे उद्योग ही ज्यादा रोजगार बनाते थे। इसलिए यदि छोटे उद्योगों में 100 कर्मी बेरोजगार हुए तो हम मान सकते हैं कि बड़े उद्योगों में 50 रोजगार बने होंगे।

चुनाव सुधार बिल पास कराने को लेकर ऐसी हड़बड़ी क्यों दिखा रही सरकार

विपक्ष के विरोध और उसकी ओर से व्यक्त की जा रही आशंकाओं के बीच जिस हड़बड़ी में चुनाव सुधार (संशोधन) विधेयक 2021 संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया, वह अच्छी मिसाल नहीं पेश करता। आधार नंबर को वोटर आईडी कार्ड से जोड़ने की बात जब से शुरू हुई है, तभी से इसके संभावित दुरुपयोग की आशंकाएं जताई जा रही हैं। इन्हीं आशंकाओं की वजह से इसका विरोध भी देखा जा रहा है। 2015 में चुनाव आयोग की तरफ से आधार डेटा के सहारे मतदाता सूची से फर्जी नाम हटाने और दोहराव मिटाने का एक पायलट प्रॉजेक्ट शुरू किया गया था। मगर सुप्रीम कोर्ट ने इस पहल पर रोक लगा दी थी। यह बात बार-बार स्पष्ट होती रही है कि आधार कार्ड का इस्तेमाल पते के सबूत के रूप तो किया जा सकता है, लेकिन इसे किसी की नागरिकता का प्रमाण नहीं करार दिया जा सकता। हालांकि मौजूदा विधेयक में आधार नंबर को वोटर आईडी कार्ड से जोड़ने की व्यवस्था को ऐच्छिक रखा गया है और इसी आधार पर सरकार इसके विरोध को अनावश्यक बता रही है, लेकिन इससे उस हड़बड़ी का औचित्य नहीं साबित होता जो बिल पास करने में दिखाई गई है। राज्यसभा में इसे विपक्ष के वॉकआउट के बाद पारित किया गया। लोकसभा में भी इस पर ठीक से बहस नहीं हो सकी। विप सांसदों को संशोधन सुझाने का मौका नहीं मिला। कई नेता कहते पाए गए कि विपक्ष के 12 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित करने का संभवतः यही उद्देश्य था कि राज्यसभा से यह बिल विपक्ष के विरोध के बावजूद आसानी से पारित करा लिया जाए। चुनाव सुधार की एक महत्वपूर्ण पहल को लेकर विपक्ष में इस तरह का अविश्वास बनने देना संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। दिलचस्प यह भी है कि कानून मंत्री ने विधेयक का समर्थन करते हुए विप सदस्यों की यह कहकर आलोचना की कि वे इस विधेयक को समझ ही नहीं पाए हैं। अगर इस आलोचना को सच मान लिया जाए, तब भी क्या सरकार के लिए यह जरूरी नहीं था कि ऐसे तमाम सदस्यों को विधेयक समझने का पूरा मौका देती, उनके साथ विस्तृत बातचीत और बहस चलाकर उन्हें पूरी जानकारी मुहैया कराती, उनकी आशंकाएं दूर करती

अगर आप सक्सेसफुल करियर बनाना चाहते हैं, तो आपके अंदर बेहतर कम्युनिकेशन स्किल का होना बेहद जरूरी है। क्योंकि एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल से आप अपने करियर को उच्च स्तर तक ले जा सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल आपकी पर्सनेलिटी का ही हिस्सा है, इसलिए अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव करने के लिए आपको अपनी कम्यूनिकेशन स्किल भी बेहतर करनी होगी।

करियर को स्पीड देने के लिए बेहतर कम्युनिकेशन स्किल जरूरी

कम्युनिकेशन स्किल बातचीत करना की एक कला है। ये बिल्कुल भी जरूरी नही है कि हर इंसान को बात करने की कला या सही तरीका आता हो। कम्युनिकेशन स्किल का डिग्री और पढ़ाई-लिखाई से भी कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि ये जरूरी नही है कि हर पढ़े-लिखे और डिग्रीधारी शख्स की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी ही हो। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखकर इसमें सुधार जरूर किया जा सकता है।

बॉडी लैंग्वेज सही रखें

यह एक तरह का नॉन-वर्बल कम्युनिकेशन होता है, जिसमें आप बिना कुछ बोले बॉडी के हाव-भाव से सब कुछ कह देते हैं। बॉडी लैंग्वेज को देखकर आप सामने वाले पर्सन के बारे में सब कुछ समझ जाते हैं, तो अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज को सही रखना जरूरी है। अपनी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा आप सामने वाले को अपनी बात आसानी से समझा सकते हैं, लोगों से बात करते समय या मीटिंग्स में जेब में हाथ डालकर या हाथों को फोल्ड करने नहीं रखना चाहिए है आपको सामने वाले को अपनी बात समझाने के लिए अपनी बॉडी लैंग्वेज का सही तरह से यूज करना चाहिए।

दूसरों की बातें ध्यान से सुनें

अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं तो आपको कोई दूसरों भी बात को भी बहुत ही ध्यान से सुनना होगा। इससे आप उसकी बातों को अच्छे से समझ सकेंगे। शुरुआत में बात करते समय आपसे कुछ गलतियां भी हो सकती हैं, लेकिन जब आप डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे तो गलतियां कम होंगी और आप सही से कम्युनिकेशन कर सकेंगे। इसीलिए किसी भी बात को अच्छे से सुनिए फिर बोलना सीखिए।

सामने वाले को समझें

अगर आप किसी से कम्युनिकेशन कर रहे है, तो आपको उसकी बातों को अच्छे से समझने के साथ उसे भी समझना होगा कि वो आपसे क्या कहना चाहता है। तभी आप उसके साथ कम्युनिकेशन कर पाएंगे। इसलिए पहले सामने वाले पर्सन की बातों को अच्छे से समझें कि वो क्या कहना चाहता है, कैसा एक्सप्रेशन दे रहा है और उसको अच्छे से समझने के बाद आप अपना जवाब दें।

सही शब्दों का प्रयोग करें

किसी से बात करते समय आपको सही शब्दों का यूज करना चाहिए। इसके लिए डेली नये शब्दों को सीखें और उन्हें लोगों से बात करते समय यूज करें। स्टार्टिंग में आपको लोगों से बात करते समय अपनी आवाज को स्लो रखना है और सही शब्दों को बोलना है, बहुत बार ऐसा होता है कि जल्दी-जल्दी में लोग कम्युनिकेशन करते समय गलत शब्दों का प्रयोग कर जाते हैं, आपको धीरे बोलना है और अपने शब्दों को स्पष्ट बोलना है। जिससे सामने वाला व्यक्ति आपकी बात को अच्छे से समझ सके।

रोज प्रैक्टिस करें

अगर आप दिल से अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी। आपको डेली कम्युनिकेशन के कुछ वर्ड्स याद करने होंगे और इन याद किये गये वर्ड्स को हफ्ते में 2 बार दोहराना होगा। क्योंकि अगर आप एक बार पढ़ने के बाद इन्हें दोबारा देखेंगे नहीं तो भूल जायेंगे। रोज थोड़ा टाइम अपनी कम्युनिकेशन पर दीजिए, डेली कुछ नये वर्ड्स सीखिए। इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होगी।

प्वॉइंट टू प्वॉइंट बात करें

चाहे आपका फ्रेंड हो या कोई अन्य व्यक्ति, किसी से भी बात करते समय ध्यान रखें कि आपको प्वॉइंट टू प्वॉइंट बात करना है। किसी से बात करना होता है तो आपको बिना डरे खुल कर बात करना चाहिए। अगर आप इधर उधर की बात करेंगे तो जिस प्वाइंट पर आप बात करना चाहते हैं, उसपर नहीं कर पाएंगे। साथ ही सामने वाला व्यक्ति भी कंफ्यूज रहेगा।

आई कांटेक्ट रखें

यह ध्यान रखें कि आप जब भी किसी से बात करें तो सामने वाले से आई कांटेक्ट बनाये रखें। इससे हमारी सिंसेरिटी और इंटरेस्ट दिखाई देता है और साथ ही हमारे इमोशन्स भी साफ-साफ दिखाई देते हैं। ये हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी इफेक्टिव बनती है। वहीं ऐसे बात करते समय आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है।

कॉफिडेंट रहें

किसी से बात करते समय कॉफिडेंट रहना जरूरी होता है। यह तभी हो पाएगा जब आप निडर होंगे, श्योर होंगे और जब आप बाहर की आवाजों पर डिपेंडेंट नहीं होंगे। इसीलिए स्टार्टिंग में जब भी आप किसी से बात करें, तो अपनी गलतियों से डरे नहीं, क्योंकि गलतियां होना एक नार्मल बात है, लेकिन जब धीरे-धीरे आप बोलना सीख लेंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो जाएगी तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ किसी भी फंक्शन में, पार्टी में, मीटिंग्स में या कहीं पर भी बोल सकेंगे।

मनोविज्ञान की फील्ड में हैं कई करियर ऑप्शन

मनोविज्ञान का क्षेत्र है, जिसमें प्रत्येक आयुवर्ग के लोग विशेषज्ञता हासिल कर अपना करियर बना सकते हैं। इसमें मानव मन और व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मसलन, मस्तिष्क तनाव में कैसे काम करता है, यह कैसे भाषा सीखता है, तथ्यों को कैसे याद रखता है या किसी भी तरह की मानसिक बीमारी इसके काम करने के तरीके को कैसे प्रभावित कर सकती है। इस सेक्टर में विशेषज्ञता और रुचियों के आधार पर मनोविज्ञान डिग्री धारकों के लिए कई अलग-अलग विकल्प उपलब्ध हैं, जो कि इस प्रकार हैं-

- मनोविज्ञानी
- मनोचिकित्सक
- समाज सेवक
- काउंसलर
- शैक्षिक मनोवैज्ञानिक
- मानव संसाधन प्रबंधक
- अध्यापक
- अनुसंधान भूमिकाएं
- मीडिया भूमिकाएं
- मनोविज्ञान में करियर

मनोविज्ञान का कोर्स करने के बाद छात्र पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ केयर, एजुकेशन, मेंटल हेल्थ स्पोर्ट्स, सोशल वर्क, थेरेपी एंड काउंसलिंग जैसे कई सेक्टर में करियर बना सकते हैं। यहां पर वे सलाहकार, अनुसंधान-आधारित, उपचार-आधारित या चिकित्सीय की भूमिका निभा सकते हैं। इसके अलावा मीडिया और अन्य रचनात्मक फील्ड में नौकरियों सहित मनोविज्ञान स्नातकों के लिए कई ऑप्शन भी हैं।

चार्टर्ड मनोवैज्ञानिक

एक चार्टर्ड मनोवैज्ञानिक के तौर पर आप व्यावसायिक मनोविज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान, खेल और मानसिक स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल कर सकते हैं। यहां आप सभी पृष्ठभूमि के लोगों, रोगियों और क्लाइंट के साथ काम कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आप कुछ मनोवैज्ञानिक मुद्दों पर बेहतर ढंग से समझने और सलाह देने के लिए आप व्यवहार, विचारों और भावनाओं का विश्लेषण कर सकते हैं। हालांकि यदि आप मनोचिकित्सक बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मेडिकल डिग्री हासिल करने की आवश्यकता होगी।

मनोचिकित्सक

एक मनोचिकित्सक के तौर आपको व्यक्तियों, जोड़ों, समूहों या परिवारों के साथ काम करता होगा। जिससे आप अपने क्लाइंट्स को भावनात्मक और रिश्ते से संबंधित मुद्दों, तनाव और यहां तक कि व्यसन सहित मनोवैज्ञानिक परेशानियों को दूर करने में मदद कर सके। इनमें संज्ञानात्मक व्यवहार विधियां, मनोविश्लेषणात्मक और मनोगतिक चिकित्सा, साथ ही कला चिकित्सा, नाटक चिकित्सा, ह्यूमनिस्टिक और एकीकृत मनोचिकित्सा, सम्मोहन-मनोचिकित्सा और अनुभवात्मक चिकित्सा शामिल हैं।

समाज सेवक

एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर आपको ऐसे लोगों की स्थितियों में सुधार लाने के लिए काम करना होगा, जो अपने जीवन में कठिन दौर से गुजर रहे हैं। ये कोई भी हो सकते हैं जैसे बच्चों या बुजुर्गों का या ऐसा ही अन्य कोई ग्रुप, विकलांग लोगों और अपराध और दुर्व्यवहार के शिकार लोगों सहित अन्य कई।
सामाजिक कार्यकर्ता स्कूलों, घरों, अस्पतालों या अन्य सार्वजनिक एजेंसियों के भीतर काम कर सकते हैं।

काउंसलर

एक काउंसलर लोगों को उनके जीवन, भावनाओं और अनुभवों के साथ बेहतर तरीके से सामंजस्य बिठाने में मदद करता है। यहां पर क्लाइंट की बातों को ध्यान से सुनना एक काउंसलर के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। एक काउंसलर में सुनने, सहानुभूति देने, सम्मान और धैर्य प्रदान करने की क्षमता साथ विश्लेषण करने की क्षमता होनी जरूरी है, ताकि क्लाइंट को उनकी स्थिति से बेहतर तरीके से निपटने में सक्षम बनाया जा सके। एक काउंसलर अक्सर विवाह और परिवार, स्वास्थ्य, दुर्व्यवहार, पुनर्वास, शिक्षा, दुख, मानसिक स्वास्थ्य, करियर मार्गदर्शन और बाल रोग सहित अनेक क्षेत्र शामिल हैं।

शिक्षा में मनोविज्ञान करियर

मनोविज्ञान कोर्स के बाद आप शिक्षा के क्षेत्र में भी जा सकते हैं। यहां आप शिक्षा के साथ-साथ शैक्षिक चिकित्सा, शैक्षिक मनोविज्ञान और शिक्षा के भीतर सामाजिक कार्य, मनोविज्ञान स्नातक प्राथमिक, माध्यमिक या कॉलेज, यूनिवर्सिटी स्तर की शिक्षा में काम कर रहे शिक्षकों के रूप में कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा जेल के अंदर के युवा अपराधियों को ठीक करने के लिए काम कर सकते हैं। वहीं महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में करियर में प्रवेश करने के लिए आपको मास्टर / पीएचडी योग्यता की आवश्यकता होगी। उच्च शिक्षा के अंतर्गत आप शिक्षण या रिसर्च दोनों ही क्षेत्र में करियर बना सकते हैं।

रिसर्च में करियर

मनोविज्ञान के तौर पर आप रिसर्च एजेंसियों, पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गनाइजेशन या विश्वविद्यालयों में रिसर्च कर सकते हैं। सभी क्षेत्रों के भीतर रिसर्च करियर और भी व्यापक हैं, इसमें सरकारी नीति विकास या उद्योग के लिए काम कर सकते हैं। आप एक चैरिटी या अन्य गैर-लाभकारी संगठन के लिए भी काम कर सकते हैं जो भाषण बाधाओं, मस्तिष्क क्षति, बाल विकास या मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य पर कानूनी और अवैध दवाओं के प्रभाव जैसी चुनौतियों को हल करने के लिए रिसर्च कर रहे हैं।

मीडिया और विज्ञापन करियर

मनोविज्ञान डिग्री होल्डरों के लिए मीडिया में भी विविध करियर हैं। मनोविज्ञान स्नातक मानव व्यवहार को लेकर कंपनी के लिए कई महत्वपूर्ण बातें बता सकते हैं। साथ ही समस्याओं का विश्लेषण करने, ध्यान से सुनने, प्रतिक्रिया देने और सहानुभूति और कारण के साथ कार्य करने की क्षमता प्रदान कर सकते हैं। इस वजह से, प्रबंधन, उत्पादन, शेड्यूलिंग और लेखन सहित सभी विभागों के भीतर मनोविज्ञान स्नातकों की मांग होती है।

मानव संसाधन और संचार करियर

मनोविज्ञान की डिग्री के साथ ह्यूमन रिसोर्स और कम्युनिकेशन करियर भी एक अच्छा विकल्प है। पब्लिक और प्राइवेट दोनों क्षेत्रों में उपलब्ध इन भूमिकाओं में कर्मचारी संतुष्टि, व्यावसायिक विकास, प्रशिक्षण, भर्ती, पीआर, पेरोल और आंतरिक संचार जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

इसरो दे रहा है फ्री ऑनलाइन कोर्सेज की पढ़ाई का मौका

अगर आप स्पेस के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं और इसरो के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो आपकी यह इच्छा पूरी हो सकती है। आप भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के फ्री ऑनलाइन कोर्सेज के साथ जुड़ सकते हैं। इसरो ने इसी साल तीन नए प्रोफेशनल कोर्सेज शुरू किए हैं, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, देहरादून द्वारा आयोजित किए जा रहे।

वर्ष 2022 में अगर आप यह कोर्स करना चाहते हैं तो आप आईआईआरएस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कोर्सेज के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, हालांकि ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो अभी बंद है। इन कोर्सेज को करने के लिए उम्मीदवारों को कोई फीस चुकाने की जरूरत नहीं होगी। तीनों कोर्स बिल्कुल फ्री हैं और कोर्स पूरा करने के बाद स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। आईआईआरएस देहरादून की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक आईआईआरएस यूट्यूब चैनल के माध्यम से पाठ्यक्रम सत्र में भाग लेने वाले छात्रों को 24 घंटे के बाद उपलब्ध ऑफलाइन सत्र के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होती है। इसरो के मुताबिक, इन ऑनलाइन लर्निंग कोर्स में प्रत्येक सिलेबस को अलग-अलग कार्यकाल में बांटा गया है, जो 4 से 12 दिनों तक चलते हैं। तीनों कोर्स को कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इसके लिए वर्तमान में कॉलेज करने वाले व्यक्ति से लेकर नौकरीपेशा तक, कोई भी व्यकित आवेदन डाल सकता है। हालांकि इसके लिए उस व्यक्ति को अपनी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से परमिशन लेनी होगी।

इसरो के फ्री ऑनलाइन कोर्सेज

मशीन लर्निंग टू डीप लर्निंग : रिमोट सेंसिंग डाटा क्लासिफिकेशन

इसरो की गाइडलाइन कहती है कि कोर्स विशेष रूप से विभिन्न एप्लिकेशन में रिमोट सेंसिंग डेटा प्रोसेसिंग में काम करने वाले पेशेवरों के लिए डिजाइन किया गया है।

अर्थ ऑब्जर्वेशन फॉर कार्बन साइकिल स्टडी

इस कोर्स को रिसर्चर्स, पेशेवरों और अर्थ ऑब्जर्वेशन, कार्बन मॉडलिंग, कार्बन असेसमेंट से जुड़े विद्यार्थियों के लिए डिजाइन किया गया है।

ओवर व्यू ऑफ जीआईएस टेक्नोलॉजी

इस टेक्नोलॉजी को जीआईएस. कहा जाता है। इसमें उम्मीदवारों को कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की मदद से भौगोलिक सूचना के साथ एकीकृत कर इनके लिए आंकड़े एकत्रण, प्रबंधन, विश्लेषण, संरक्षण और निरूपण की व्यवस्था करने के लिए डिजाइन किया गया है।

इस तरह कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन

अगर आप अलगे सत्र में इसरो फ्री ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो आपको इसरो या आईआईआरएस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए, छात्र का पूरा नाम, कक्षा 10वीं की मार्कशीट या सर्टिफिकेट, ईमेल और पासवर्ड, वे जिस कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं, उसका चयन करना होगा, पर्सनल डीटेल्स, एजुकेशन डीटेल्स और जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। कोर्स पूरा होने के बाद प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए, एक छात्र को ई-क्लास पोर्टल के माध्यम से 70% सत्रों में भाग लेना होगा।

लिखने के शौकीन हैं तो मिल सकती है दिलचस्प जॉब

क्रिएटिव राइटिंग सिर्फ शौक ही नहीं, करियर भी बन सकता है। इसी के साथ जुड़ा हुआ है एक और करियर, जो है ट्रांसलेटर यानी अनुवादक का। इसके लिए तो अनेक संस्थानों में काफी स्कोप रहता है।

कहां है मांग ?

रेलवे, बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों (पीएसयू) आदि में अनुवादकों की अच्छी डिमांड रहती है। आप चाहें, तो फ्रीलांसर के तौर पर भी काम कर सकते हैं। वहीं इंटरप्रेटर के रूप में खुद को तैयार करके आप विभिन्न देशों के दूतावासों तथा विदेशी कंपनियों में जॉब पा सकते हैं। यह एक दिलचस्प जॉब है, जिसमें हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है।
अभ्यास बहुत जरूरी लेखक बनने का हुनर कई लोगों में जन्मजात होता है मगर इस हुनर को मांजना बहुत जरूरी है। हर लिखने वाला प्रभावशाली नहीं होता। अगर आप भी बतौर क्रिएटिव राइटर करियर बनाना चाहते हैं, तो सरल, सहज और प्रभावी लिखने का अभ्यास करते रहें। पुराने क्लासिक्स से लेकर नए, प्रमुख लेखकों की किताबें तथा पत्र-पत्रिकाओं मे छपने वाले उनके कॉलम जरूर पढ़ते रहें। आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे, उतना ही आपका लेखन निखरेगा। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप सीखें सबसे लेकिन लिखते समय अपनी मौलिक पहचान जरूर बनाए रखें। आपके लेखन में किसी अन्य लेखक की नकल या प्रभाव नहीं दिखना चाहिए।
मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज में आईटीआई पास के लिए वैकेंसीज

कहां से पढ़ें ?

यदि आप करियर के तौर पर क्रिएटिव राइटिंग या ट्रांसलेशन को अपनाना चाहते हैं, तो बेहतर होगा कि आप इसके लिए बाकायदा कोर्स कर लें। क्रिएटिव राइटिंग का कोर्स इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय तथा अन्य प्रमुख विश्वविद्यालयों से किया जा सकता है। वहीं ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर बनने के लिए आपको केंद्रीय हिंदी संस्थान या किसी अन्य आधिकारिक संस्थान से अनुवाद का कोर्स करना होगा।

न्यूज ब्रीफ

तालिबान को करोड़ों की चपत : गलती से ताजिकिस्तान भेजे 8 लाख डॉलर

काबुल। तालिबान हुकूमत ने सितंबर में गलती से ताजिकिस्तान स्थित अपनी एम्बेसी के अकाउंट में 8 लाख डॉलर ट्रांसफर कर दिए। गलती का एहसास होने के बाद जब तालिबान से पैसा वापस मांगा तो वहां से इसे लौटाने से इनकार कर दिया गया। अशरफ गनी सरकार के वक्त ताजिकिस्तान में नियुक्त किए गए राजदूत मोहम्मद जहीर अघबर कहा- पिछली सरकार ने यह पैसा आने वाले खर्चों और कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए मंजूर किया था। अघबर ने बताया- अशरफ गनी सरकार को यह पैसा अफगान एम्बेसी के खाते में भेजना था, लेकिन तालिबान के कब्जे के बाद अशरफ गनी देश छोड़कर चले गए और हालात बदल गए। हम तालिबान को पैसा नहीं लौटा सकते, यह पैसा एम्बेसी की जरूरत के हिसाब से खर्च किया गया है। इसका इस्तेमाल ताजिकिस्तान में शरणार्थी बच्चों के स्कूल पर होना था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि एम्बेसी के अकाउंट में 4 लाख डॉलर ही ट्रांसफर किए गए थे। शुरुआत में तो तालिबान ने इस मामले पर कुछ नहीं कहा, लेकिन नवंबर में जब देश के हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए तो इसके बाद रकम वापस मांगने के लिए ताजिकिस्तान से संपर्क किया गया। जब तालिबान ने पैसा लौटाने को कहा तो ताजिक अधिकारियों से साफ तौर पर इससे इनकार कर दिया।

दुबई के किंग का सबसे महंगा तलाक : देने होंगे 5500 करोड़

दुबई। दुबई के किंग शेख मोहम्मद बिन राशिद अल-मकतूम ने अपनी पत्नी राजकुमारी हया से तलाक ले लिया है। इसके एवज में उन्हें लगभग 5500 करोड़ रुपए (554 मिलियन पाउंड) राजकुमारी को देने होंगे। ब्रिटेन की हाई कोर्ट ने किंग को इसके लिए आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि किंग को यह रकम डिवोर्स सेटलमेंट और बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए अदा करनी होगी। यह सेटलमेंट ब्रिटिश कानूनी इतिहास के सबसे बड़े सेटलमेंट में से एक है। राजकुमारी हया जॉर्डन के पूर्व राजा हुसैन की बेटी हैं। हाई कोर्ट के जज फिलिप मूर ने अपने फैसले में कहा कि राजकुमारी हया और उनके बच्चों को आतंकवाद या फिर अपहरण जैसे खतरों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे हालात में उनकी सुरक्षा के लिए खास इंतजाम होने चाहिए। ब्रिटेन में उन्हें खास सुरक्षा की जरूरत है।

राजकुमारी को तुरंत मिलेंगे 2500 करोड़ रुपए

वकीलों के मुताबिक, शेख की ओर से दी जाने वाली रकम में से 2500 करोड़ रुपए (251.5 मिलियन पाउंड) राजकुमारी हया को एकमुश्त दिए जाएंगे। उनके दोनों बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए 2900 करोड़ रुपए (290 मिलियन पाउंड) सिक्योरिटी के तौर पर बैंक में रखे जाएगे। इसके अलावा बच्चों के बड़े होने पर हर साल 112 करोड़ रुपए (11.2 मिलियन पाउंड) देने होंगे। राजकुमारी हया ने इस सेटलमेंट के लिए लगभग 14 हजार करोड़ रुपए (1.4 बिलियन पाउंड) मांगे थे।

अंटार्कटिका में बर्फ के 200 मीटर नीचे मिला जीवन, खोजी गईं 77 नई प्रजातियां

आईटीडीसी इंडिया ई-प्रेस/ आईटीडीसी न्यूज लंदन

अंटार्कटिका की बर्फ की परत के नीचे, जैसे-जैसे आप गहराई की ओर बढ़ेंगे जीवन के लिए वातावरण मुश्किल होता जाएगा। एक स्थान पर जाकर यह वातावरण बेहद ठंडा और घोर अंधेरे से भरा हो जाता है, जहां भोजन के स्रोत लगभग न के बराबर होते हैं। हालांकि पृथ्वी पर ऐसे जीव पाए जाते हैं जो कठोरतम वातावरण में भी जिंदा रह सकते हैं। लेकिन इस बिंदु पर जीवन की कल्पना करना वाकई बहुत मुश्किल है। इसके

बावजूद वैज्ञानिकों को इस क्षेत्र में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका की चरम परिस्थितियों में 77 प्रजातियों की चौंकाने वाली खोज की है। सबूत तो इस बात के भी मिले हैं कि ये जीवन के सबूत करीब 6000 साल पुराने हैं। जर्मनी की रिसर्च में पता चला है कि इन प्रजातियों में तलवार के आकार के शैवाल जीव और कुछ असामान्य कीड़े शामिल हैं। गर्म पानी का इस्तेमाल करते हुए अल्फ्रेड वेगेनर इंस्टीट्यूट की टीम ने दो करीब 200 मीटर (656 फीट) गहरे दो गड्ढे किए थे।

सतह पर पाए जाने वाले जीवों की तुलना में ज्यादा समृद्ध

खुले समुद्र से कई मील दूर होने के बावजूद वैज्ञानिकों ने अत्यंत समृद्ध जैव विविधता वाले नमूनों को इकट्ठा किया है। बल्कि यह महाद्वीपीय शेल्फ के ऊपर पाए जाने वाले कुछ नमूनों की तुलना में ज्यादा समृद्ध हैं, जहां प्रकाश और भोजन दोनों पाए जाते हैं। शोधकर्ताओं ने कहा कि समुद्र तल से पाए गए जीवन के अवशेष असाधारण और अप्रत्याशित हैं। इन 77 प्रजातियों में तलवार के आकार ब्रायोज़ोअन जैसे मेलिसेरिटा ओब्लिका और सर्पुलिड कीड़े जैसे पैरालाओस्पिरा सिकुला शामिल हैं। ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण में समुद्री जीवविज्ञानी और प्रमुख शोधकर्ता डॉ डेविड बर्नेस ने कहा कि चरम परिस्थितियों में पाया गया जीवन एक आश्चर्यजनक खोज है। यह हमें बताता है कि अंटार्कटिका का समुद्री जीवन कितना अनोखा और खास है।

बिल गेट्स की डराने वाली चेतावनी:

दुनिया महामारी के सबसे बुरे दौर की तरफ बढ़ रही, मैंने सभी हॉलिडे प्लान कैंसिल किए

आईटीडीसी इंडिया ई-प्रेस/ आईटीडीसी न्यूज वाशिंगटन

दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने ओमिक्रॉन वैरिएंट को लेकर चेतावनी दी है। गेट्स ने संक्रमण को लेकर लगातार एक के बाद एक 7 ट्वीट किए। उन्होंने आशंका जताई है कि हम जल्द ही महामारी के सबसे बुरे दौर से गुजर सकते हैं। बिल गेट्स ने कहा है कि उनके करीबी दोस्त तेजी से नए संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं, इसलिए लोगों को सावधान रहना चाहिए। नए वैरिएंट के खतरे को देखते हुए उन्होंने छुट्टियों पर बाहर घूमने जाने के अपने सभी प्लान कैंसिल कर दिए हैं। गेट्स ने मास्क पहनने, वैक्सीन लगवाने और भीड़ न लगाने की सलाह दी है।

ओमिक्रॉन की संक्रमण दर ज्यादा

उन्होंने आगे कहा कि ओमिक्रॉन वैरिएंट को लेकर सतर्क रहना जरूरी है। दूसरे संक्रमण की तुलना में ओमिक्रॉन बेहद तेजी से फैल रहा है। जल्द ही यह दुनिया के हर देश में पहुंच जाएगा। हमें इसके बारे में फिलहाल ज्यादा जानकारी भी नहीं है।

बिल गेट्स ने आगे कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि ओमिक्रॉन हमें कितना बीमार करता है, यह भी नहीं पता है। अगर यह डेल्टा से मुकाबले इसे आधा भी असरदार मानें तो यह चिंता की बात है, क्योंकि यह बेहद तेजी से फैलता है।

अमेरिका में बढ़ रहे ओमिक्रॉन केस

बिल गेट्स की चेतावनी ऐसे समय में आई है, जब अमेरिका में ओमिक्रॉन वैरिएंट के नए केस तेजी से बढ़ रहे हैं। वहां पिछले एक सप्ताह में कोरोना के कुल मामलों में 73 प्रतिशत नए मरीज ओमिक्रॉन वैरिएंट के मिल रहे हैं। पहले यह संख्या 3 फीसदी थी।

पॉजिटिव नोट के साथ खत्म की बात

आखिर में बिल गेट्स ने कहा कि इस बीच एक अच्छी खबर यह है कि ओमिक्रॉन बेहद तेजी से आगे बढ़ता है। किसी देश में फैलने के बाद संक्रमण की लहर 3 महीने से भी कम समय में खत्म हो जाती है। उन्होंने कहा कि दुनिया हमेशा ऐसी नहीं रहेगी। एक दिन महामारी खत्म होगी। हम एक दूसरे की देखभाल करें तो यह समय जल्दी आएगा।

जर्मनी में बिना दर्शकों के होंगे फुटबॉल मैच, ब्रिटेन में क्रिसमस से पहले नहीं लगेगा कोई प्रतिबंध

यूरोप में कोरोना के बढ़ते मामलों और नए वैरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर चिंता के बीच नए प्रतिबंधों का ऐलान किया है। जर्मनी में 28 दिसंबर से फुटबॉल समेत बड़े इवेंट बिना दर्शकों के करने पर 16 राज्यों ने सहमति जताई है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने नए साल के जश्न को लेकर निजी समारोह को लेकर भी नए नियमों की जानकारी दी। इसके तहत एक स्थान पर 10 वैक्सीनेटेड लोगों के जुटने पर सहमति जताई गई। वहीं ब्रिटेन में क्रिसमस से पहले किसी भी प्रकार के प्रतिबंधों को लेकर मंत्री सहमत नहीं दिखे। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने सोमवार को कोरोना के नए डेटा पर चर्चा करने के लिए अपने कैबिनेट के साथ दो घंटे से अधिक की बैठक की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुछ वैज्ञानिकों की चेतावनियों के बावजूद कई मंत्रियों ने क्रिसमस से पहले नए प्रतिबंधों की संभावनाओं पर आपत्ति जताई।

हेलिकॉप्टर हो गया था क्रैश, मेडागास्कर के मंत्री ने 12 घंटे समुद्र में तैरकर बचाई जान

अंतानानारिवो

कहते हैं कि मुश्किल चाहे जितनी बड़ी क्यों न हो, इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए। कुछ यही देखने को मिला अफ्रीकी देश मेडागास्कर में। मेडागास्कर का एक बचाव हेलिकॉप्टर समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हेलिकॉप्टर पर देश के पुलिस मामलों के मंत्री सर्जे गेल्ले भी सवार थे। मंत्री सर्जे करीब 12 घंटे तक समुद्र में तैरते रहे और अंततः अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। यह बचाव हेलिकॉप्टर देश के पूर्वोत्तर तट पर मालवाहक जहाज के डूबने के बाद राहत और बचाव के लिए गया था। इस मालवाहक जहाज पर 130 यात्री अवैध रूप से सवार थे जिसमें से कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई है। मंत्री सर्जे गल्ले हेलिकॉप्टर के क्रैश होने के बाद बच गए और समुद्र में करीब 12 घंटे तक तैरते रहे। सुरक्षित तट पर पहुंचने के बाद मंत्री ने कहा, %यह मेरे मरने का समय नहीं है। बाद में बचाव दल ने उनके हेलिकॉप्टर के अवशेष को समुद्र के तलहटी से बरामद कर लिया। मंत्री ने कहा, %मैं जिंदा हूं, मैं महांबो सुरक्षित वापस आ गया हूं और सभी मछुआरों तथा महांबो गांव के लोगों का शुक्रगुजार हूं। मैंने कल सुबह 7:30 बजे से तैरना शुरू किया था और आज सुबह 7:30 बजे तक तैरता रहा। हेलिकॉप्टर पर दो अन्य सुरक्षा अधिकारी तैनात थे और वे भी बच गए हैं।

डॉलर की खातिर अमेरिका के चरणों में गिरे थे मुशर्रफ, पाकिस्तानियों को भी लूटा

आईटीडीसी इंडिया ई-प्रेस/ आईटीडीसी न्यूज इस्लामाबाद

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने उस सच को कबूल कर लिया है जिसे पाकिस्तानी सैन्य तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ लंबे समय से छिपाए हुए थे। प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंगलवार को अमेरिका के अफगानिस्तान में 20 साल लंबे चले आतंक के खिलाफ युद्ध में पाकिस्तान के शामिल होने के फैसले पर अफसोस जताया। इमरान खान ने यह भी कहा कि ये फैसला जनहित में नहीं बल्कि धन पाने के लिए लिया गया था। साथ ही इमरान ने इसे खुद ही अपने आप को दिया गया जख्म करार दिया।अफगानिस्तान में दो दशक चले युद्ध में पाकिस्तान की भागीदारी के आलोचक रहे खान ने दावा किया कि वह वर्ष 2001 में निर्णय लेने वालों के करीबी थे, जब तत्कालीन सैन्य शासक जनरल परवेज मुर्शरफ ने आतंक के खिलाफ युद्ध का हिस्सा बनने का निर्णय लिया था। इस्लामाबाद में विदेश मंत्रालय के अधिकारियों को संबोधित करते हुए इमरान खान ने यह बयान दिया। यही नहीं इसी वित्तीय वर्ष में मुशर्रफ ने यूएई में भी करीब 20 करोड़ पाकिस्तानी रुपये का फ्लैट खरीदा था। मजेदार बात यह है कि इसी साल उन्हें सेना से रिटायरमेंट के बाद मात्र 2 करोड़ रुपये का वित्तीय लाभ दिया गया था। पाकिस्तान के चुनाव आयोग के पास वर्ष 2013 में दाखिल किए गए दस्तावेजों में कहा गया है कि मुशर्रफ ने सेना से रिटायर होते समय मिले घर या अपनी एक भी जमीन को बेचा नहीं था। जनरल मुशर्रफ वर्ष अप्रैल 2009 में न्यायपालिका की बहाली के बाद देश छोड़कर चले गए थे।

पैसे के लिए अपने देश के सम्मान का सौदा किया

इमरान खान ने कहा, इसलिए, मैं इस फैसले के पीछे के विचार से अच्छी तरह वाकिफ था। दुर्भाग्यवश, पाकिस्तान के लोगों का हित ध्यान में नहीं रखा गया। उन्होंने कहा, हम खुद ही इसके लिए जिम्मेदार हैं, जिस तरह हमने अन्य लोगों को अपना इस्तेमाल करने दिया और पैसे के लिए अपने देश के सम्मान का सौदा किया। हमने ऐसी विदेश नीति बनायी जोकि जनहित के खिलाफ रही। बता दें कि पाकिस्तान की गरीब जनता को लूटकर अरबों की दौलत बनाने वाले मुशर्रफ पोल एक-एक करके अब खुलती जा रही है। पाकिस्तान के दिलेर पत्रकार अहमद नूरानी ने पिछले दिनों खुलासा किया था कि जनरल परवेज मुशर्रफ को रिटायरमेंट पर दो करोड़ रुपये मिले थे लेकिन उन्होंने लंदन और संयुक्त अरब अमीरात में 20-20 करोड़ रुपये दो फ्लैट खरीदे। नूरानी ने अपनी वेबसाइट फैक्ट फोकस पर जारी रिपोर्ट में ब्रिटेन और यूएई के दस्तावेजों के हवाले से बताया कि मुशर्रफ ने लंदन में 13 मई 2009 को करीब 20 करोड़ रुपये में फ्लैट खरीदा था।

निलंबित राज्यसभा सांसदों ने नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में अपने निलंबन को रद्द करने की मांग करते हुए महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन किया।

अहमदाबाद में एसपी रिंग रोड पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर का एक हिस्सा गिर गया।

नाटो ने दिखाया आक्रामक व्यवहार तो रूसी सेना देगी करारा जवाब : पुतिन

आईटीडीसी इंडिया ई-प्रेस/ आईटीडीसी न्यूज मास्को

यूक्रेन को लेकर चल रहे विवाद के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नाटो को कड़ी चेतावनी दी है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अगर पश्चिम अपनी 'आक्रामक' नीति जारी रखता है लेकिन बातचीत के लिए तैयार है, तो उनका देश जवाबी कार्रवाई करेगा। रूस ने यूक्रेन की सीमा पर करीब 1 लाख सैनिकों को तैनात कर रखा है। अमेरिका ने आरोप लगाया है कि रूस यूक्रेन पर हमले की तैयारी कर रहा है। पुतिन ने रूसी रक्षा मंत्रालय बोर्ड की विस्तारित बैठक में कहा, 'अगर हमारे पश्चिमी सहयोगी अपनी स्पष्ट रूप से आक्रामक नीति जारी रखते हैं, तो हम शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों का दृढ़ता से जवाब देने के लिए पर्याप्त जवाबी सैन्य-तकनीकी का इस्तेमाल करेंगे।' समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने रोमानिया और पोलैंड सहित रूसी सीमाओं के पास अमेरिकी मिसाइल रक्षा प्रणालियों की तैनाती पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, 'हमें रूस की सुरक्षा और संप्रभुता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है।'

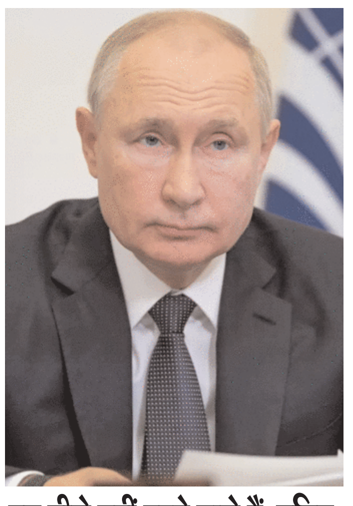

हम पीछे नहीं हटने वाले हैं: पुतिन

रूसी राष्ट्रपति ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) यूक्रेन में मिसाइलें तैनात करते हैं, तो वे केवल 7 से 10 मिनट में मास्को पहुंचेंगी और अगर वे हाइपरसोनिक हथियार हैं तो सिर्फ 5 मिनट में पहुंचेंगे। पुतिन ने कहा, 'उन्हें समझना चाहिए कि हम पीछे नहीं हटने वाले हैं।' रूस ने हाल ही में नाटो को एक मसौदा समझौता भेजा है और पश्चिमी देशों के लिए यूरोप में सुरक्षा गारंटी पर अमेरिका को एक मसौदा संधि पर विचार करने के लिए भेजा है। पुतिन ने कहा कि रूस सशस्त्र संघर्ष और रक्तपात के खिलाफ खड़ा है और कूटनीति के माध्यम से मुद्दों को हल करना चाहता है, लेकिन स्पष्ट कानूनी गारंटी होनी चाहिए। पुतिन ने फिर कहा कि उन्हें अमेरिका और उसके सहयोगी देशों से यह आश्वासन चाहिए कि नाटो पूर्व की ओर अपना विस्तार नहीं करेगा। इसके साथ ही पुतिन ने यूरोप में बढ़ते तनाव के लिए पश्चिमी देशों को जिम्मेदार ठहराया। रूस के उच्च सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक में पुतिन ने यह बयान ऐसे समय दिया है जब कुछ दिन पहले पहले ही मास्को ने यूक्रेन तथा अन्य पूर्व सोवियत देशों को नाटो की सदस्यता नहीं देने संबंधी मसौदा सुरक्षा दस्तावेज पेश किये हैं।

न्यूज ब्रीफ

जोफ्रा आर्चर का हुआ दूसरा ऑपरेशन, वेस्टइंडीज के खिलाफ नहीं खेलेंगे

लंदन। इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने कहा कि तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने अपनी चोटिल दाहिनी कोहनी का दूसरा ऑपरेशन करवाया है और वह अगली गर्मियों तक क्रिकेट से दूर रहेंगे। इंग्लैंड के इस तेज गेंदबाज की अनुपस्थिति वर्तमान की एशेज सीरीज के दौरान भी खल रही है। उनका 11 दिसंबर को लंदन में ऑपरेशन किया गया। ईसीबी ने बयान में कहा, 'यह ऑपरेशन उनकी दाहिनी कोहनी में लंबे समय से चले आ रहे दर्द को समाप्त करने के लिए किया गया।% यह 26 वर्षीय तेज गेंदबाज पिछले 9 महीनों से शीर्ष स्तर की क्रिकेट में नहीं खेला है। वह मार्च में वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भी नहीं खेल पाएंगे। आर्चर की कोहनी का मई में इंडियन प्रीमियर लीग से हटने के बाद ऑपरेशन किया गया था। उन्हें इंग्लिश काउंटी चैंपियनशिप मैच में ससेक्स के लिए गेंदबाजी करते समय उसी हिस्से में फिर से दर्द महसूस हुआ था।

लखनऊ के सहायक कोच बने विजय दहिया

नई दिल्ली। पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज विजय दहिया को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2022 से पहले बुधवार को लखनऊ फ्रेंचाइजी का सहायक कोच नियुक्त किया गया। हरियाणा के रहने वाले 48 वर्षीय दहिया उत्तर प्रदेश टीम के मौजूदा कोच हैं। उन्होंने इससे पहले दो बार आईपीएल जीतने वाली टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के सहायक कोच के रूप में काम किया है। उन्होंने दिल्ली रणजी टीम को कोचिंग देने के अलावा दिल्ली कैपिटल्स में भी प्रतिभा तलाशने के लिये' टैलेंट स्काउट के रूप में काम किया है। भारत की तरफ से दो टेस्ट और 19 एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले दहिया ने यहां जारी बयान में कहा, ''लखनऊ आईपीएल फ्रेंचाइजी के साथ काम करने का मौका से मिलने से मैं खुश और आभारी हूं। लखनऊ टीम आरपीएसजी समूह का हिस्सा है। वह पहले ही एंडी फ्लावर को मुख्य कोच और गौतम गंभीर को मेंटर (मार्गदर्शक) के रूप में नियुक्त कर चुकी है।

पंजाब ने उत्तर प्रदेश को शूटआउट में हराकर जीती राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप

पुणे। पंजाब ने उत्तर प्रदेश को पेनल्टी शूटआउट में 2-1 से हराकर मंगलवार को यहां 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता। दोनों टीम निर्धारित समय तक गोल करने में नाकाम रही जिसके बाद पेनल्टी शूटआउट का सहारा लिया गया। पंजाब के गोलकीपर कमलबीर सिंह मैच के नायक बने। उन्होंने शूटआउट में 4 बचाव करके अपनी टीम को खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई। इस बीच कर्नाटक ने तीसरे स्थान के प्लेऑफ मैच में महाराष्ट्र को 5-2 से हराया।

जब सवाल के जवाब में बोले BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली, पत्नी और गर्लफ्रेंड ही देती है तनाव

आईटीडीसी इंडिया ई-प्रेस/ आईटीडीसी न्यूज नई दिल्ली

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष और पूर्व कप्तान सौरव गांगुली हाल ही में विराट कोहली को वनडे टीम की कप्तानी से हटाए जाने के बाद काफी सूर्खियों में थे। इस फैसले से जहां कुछ लोग उनके साथ थे तो कुछ उनके खिलाफ भी थे। अब गांगुली का तनाव से दूर रहने वाला एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा कि जीवन में पत्नी और गर्लफ्रेंड ही तनाव देती है। गुड़गांव में एक इवेंट में उनसे पूछा गया कि उन्हें किस खिलाड़ी का एटीट्यूड सबसे अच्छा लगता है। सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने जवाब दिया, मुझे विराट कोहली का रवैया पसंद है लेकिन वह बहुत लड़ते हैं। गांगुली से यह भी पूछा गया कि वह जीवन में तनावों से कैसे निपटते हैं। इस पर गांगुली ने मजाकिया अंदाज में कहा कि जीवन में कोई तनाव नहीं है। केवल पत्नी और प्रेमिका ही तनाव देते हैं। गांगुली द्वारा कही गई ये बात वायरल हो रही है। गौर हो कि टी20 वर्ल्ड कप से पहले विराट कोहली ने खुद टी20 कप्तानी छोड़ने का फैसला किया

था। इसके बाद वनडे कप्तानी छिनने के बाद कई बातें सामने आईं। गांगुली ने भी स्पष्ट किया था कि उन्होंने कोहली को टी20 टीम की कप्तानी ना छोड़ने के लिए कहा था। उनके टी20 टीम की कप्तानी छोड़ने के बाद चयनकर्ताओं ने उन्हें वनडे कप्तानी से हटाने का फैसला लिया क्योंकि वह सीमित ओवरों के खेल में अलग-अलग कप्तान नहीं चाहते। वहीं कोहली ने कहा था कि उनसे इस बारे में बात नहीं हुई और वनडे कप्तानी से हटाए जाने से 1.30 घंटे पहले वनडे कप्तानी से हटाए जाने के बारे में बताया गया था।

अफ्रीक्री कप्तान की बल्लेबाजों को सलाह

बुमराह से सावधान रहें, वो खतरनाक गेंदबाज टीम इंडिया को हल्के में लेने की भूल न करें

> विदेशी दौरों पर भारत की गेंदबाजी में काफी सुधार हुआ है। हम जिस गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ खेलने जा रहे हैं उसके खिलाफ काफी सावधान रहना होगा।
>
> **डीन एल्गर, साउथ अफ्रीका के कैप्टन**

आईटीडीसी इंडिया ई-प्रेस/ आईटीडीसी न्यूज नई दिल्ली

भारत के साथ टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले साउथ अफ्रीका के कप्तान डीन एल्गर ने बल्लेबाजों को चेतावनी देते हुए कहा है कि जसप्रीत बुमराह से सावधान रहें। बुमराह खतरनाक गेंदबाज हैं। उन्होंने कहा है कि टीम इंडिया को हल्के में लेने की भूल न करें। हाल के सालों में विदेशी परिस्थितियों में भारतीय टीम के प्रदर्शन में काफी सुधार हुआ है। डीन एल्गर ने कहा, भारत पिछले दो से तीन सालों से काफी अच्छी टीम रही है और हाल के सालों में उसने विदेशों में अच्छा प्रदर्शन किया है। विदेशी दौरों पर भारत की गेंदबाजी में काफी सुधार हुआ है। हम जिस गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ खेलने जा रहे हैं उसके खिलाफ काफी सावधान रहना होगा। वहीं अनुभवी गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन को दक्षिण अफ्रीका में ज्यादा सफलता नहीं मिली है लेकिन वह विश्व क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ स्पिनरों में से एक हैं। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच 26 दिसंबर से सेंचूरियन के स्पोर्ट्स पार्क में शुरू होगा। विराट कोहली की कप्तानी वाली भारतीय टीम इन दिनों दक्षिण अफ्रीका में है और बायो- बबल में रहकर जमकर अभ्यास कर रही है। इस साल टीम इंडिया ने जिस तरह से टेस्ट में प्रदर्शन किया है उसे देखते हुए वह दक्षिण अफ्रीका उसकी सरजमीं पर कड़ी टक्कर दे सकती है।

बुमराह साउथ अफ्रीका में पिछले दौरे पर ले चुके हैं 25 विकेट

साल 2018 में दक्षिण अफ्रीका दौरे पर जसप्रीत बुमराह ने अपने टेस्ट करियर का आगाज किया था। उसके बाद से वह लगातार शानदार प्रदर्शन करने में सफल रहे हैं। मौजूदा समय में बुमराह दुनिया के सबसे सफल गेंदबाजों में शामिल हैं। बुमराह साल 2021 में 8 टेस्ट मैचों में 25 विकेट चटकाने में सफल रहे हैं।

टेस्ट सीरीज से पहले दक्षिण अफ्रीका को झटका

भारत के खिलाफ शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज से पहले दक्षिण अफ्रीकी टीम को जबरदस्त झटका लगा है। उसके चोटी के गेंदबाज एनरिक नॉर्खिया चोट की वजह से शुरुआती मैच से बाहर हो गए हैं। उनके न खेलने से दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी का आक्रमण कमजोर हुआ है। इस साल नॉर्खिया ने अपनी टीम के लिए शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने साल 2021 में अब दक्षिण अफ्रीका के लिए 5 टेस्ट मैचों में 25 विकेट झटके हैं। आगामी टेस्ट मैच में एल्गर को उनकी कमी जरूर खलेगी।

खेलो इंडिया वूमेन हॉकी लीग (अंडर-21)-2021

म.प्र. हॉकी अकादमी 12 अंकों के साथ बी में दूसरे स्थान पर

आईटीडीसी इंडिया ई-प्रेस/ आईटीडीसी न्यूज भोपाल

नई दिल्ली में 15 से 21 दिसम्बर, 2021 तक मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में खेली गई खेलो इंडिया वूमेन हॉकी लीग (अंडर-21) में आज मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी का मुकाबला हरियाणा हॉकी अकादमी से हुआ। दोनों टीमों के मध्य रोमांचक मुकाबला हुआ और दोनों ही टीमें 1-1 से बराबरी पर रही। अब तक खेले गए छह मुकाबलों में शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए मप्र हॉकी अकादमी ने 22 गोल किए है। म.प्र. हॉकी अकादमी के तीन मुकाबले ड्रा रहे और तीन मुकाबले में अकादमी ने जीत दर्ज की। मैच जीतने पर 3 अंक और ड्रा होने पर एक अंक मिलते है। म.प्र. हॉकी अकादमी ग्रुप-बी में 12 अंको के साथ दूसरे स्थान पर रही। हरियाणा हॉकी अकादमी 16 अंकों के साथ प्रथम स्थान पर है। हरियाणा हॉकी अकादमी ने छह में से पाँच मैच जीते और एक ड्रा रहा। मंगलवार को खेले गए मुकाबले के पहले हॉफ में दोनों ही टीमें कोई गोल नहीं कर सकी। मैच के दूसरे हॉफ में मप्र हॉकी अकादमी की खिलाड़ी साधना सेंगर ने 20वें मिनिट में फील्ड गोल कर टीम को 1-0 से आगे कर दिया। मैच के तीसरे हॉफ में हरियाणा हॉकी अकादमी की खिलाड़ी ज्योति ने 34वें मिनिट में फील्ड गोल कर अपनी टीम को 1-1 से बराबरी पर ला दिया। मैच के चौथे और अंतिम हॉफ में दोनों ही टीमें कोई गोल नहीं कर सकी और मुकाबला 1-1 से बराबरी पर रहा।

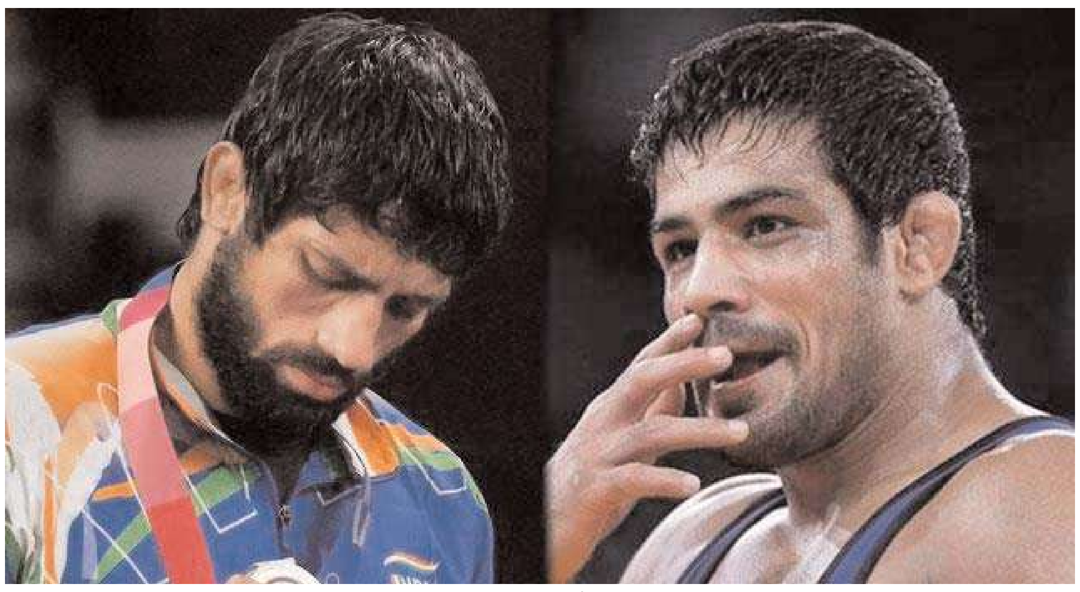

सुशील कुमार का एक मामले में फंसना भारतीय कुश्ती की प्रतिष्ठा के लिए करारा झटका था लेकिन ओलंपिक में रवि दहिया का उदय और टोक्यो खेलों में बजरंग पूनिया की अपेक्षित सफलता ने वर्ष 2021 में इस खेल को रसातल में जाने से रोक दिया। विनेश फोगाट का ओलंपिक पदक जीतने का सपना फिर से पूरा नहीं हो पाया लेकिन इस साल भारतीय कुश्ती को अंशु मलिक के रूप में नई नायिका भी मिली जिन्होंने विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचकर इतिहास रचा।

SUPER HERO

यदि आप

किसी भी व्यक्ति को जानते हैं
जिसने, सामाजिक सरोकार में
असाधारण प्रदर्शन किया हो,
वह व्यक्ति आप स्वयं भी हो सकते हैं,
दोनों स्थिति में हमें पूर्ण विवरण, भेजें।

हम देश के असली नायक
SUPER HERO MP 2021
SUPER HERO IND 2021
खोज रहे हैं, उन्हें समाज, राष्ट्र के सामने लाना और
सम्मान दिलवाना, आपका-हमारा संयुक्त प्रयास रहेगा।

Contact: Editorial Desk (Lifestyle),
ITDC News, 9826 220022
Email: responseitdc@gmail.com

PRESS ITDC
ITDC NEWS

क्रिकेट के लिए कुर्बानी देने वाले 'द्रोणाचार्य' की कहानी

सरकारी नौकरी छोड़ दी ताकि देश के लिए क्रिकेटर तैयार कर सकें, अब दो खिलाड़ी अंडर-19 में

आईटीडीसी इंडिया ई-प्रेस/ आईटीडीसी न्यूज नई दिल्ली

अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा हो चुकी है। इस टीम में UP के गाजियाबाद स्थित त्रिलोकी नाथ क्रिकेट एकेडमी के दो खिलाड़ी विकेटकीपर बल्लेबाज आराध्य यादव और बल्लेबाज सिद्धार्थ यादव का चयन हुआ है। इस एकेडमी के मुख्य कोच दिल्ली के अजय शर्मा हैं। अजय शर्मा ने सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन से साल 2016 में VRS लेकर गाजियाबाद में क्रिकेट एकेडमी की शुरुआत की, ताकि खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा मिले और उन्हें दिल्ली जाने में समय बर्बाद न करना पड़े। अजय शर्मा बताते हैं कि वह सोनेट क्लब में

तारक सिन्हा सर के साथ सहायक कोच थे। आराध्य यादव के पिता अजय यादव के साथ उनकी मुलाकात टूर्नामेंट के दौरान हुई। आराध्य के पिता दिल्ली पुलिस में हैं। वह चाहते थे कि उनके दोनों बेटे बेहतर क्रिकेटर बनें। आराध्य का बड़ा भाई अंकित यादव भी ओपनर बल्लेबाज है। मेरे पास ये दोनों बच्चे कभी-कभी आने लगे। हालांकि, जॉब की वजह से मैं ज्यादा समय नहीं दे पाता था। दोनों बच्चे काफी टैलेंटेड थे। मुझे लगा कि इन बच्चों को सही से गाइडेंस मिलेगा तो ये बच्चे इंडिया खेल सकते हैं।

बेटे को जॉब की वजह से नहीं दे पाए टाइम

मेरा बेटा मनन शर्मा भी दिल्ली से रणजी खेल चुका है और वह 2010 में अंडर-19 में टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व कर चुका है। मुझे लगता है कि शायद वह और ध्यान देता तो वह टीम इंडिया के लिए खेल सकता था। मैं आराध्य और अंकित में अपने बेटे को देखता था। मैं नहीं चाहता था कि इन बच्चों की कोचिंग में कोई कमी रहे। ऐसे में मैने 2016 में जॉब छोड़ कर पूरा समय देने की योजना बनाई।

2016 में एकेडमी की शुरुआत

आराध्य के पिता जो दिल्ली पुलिस में थे। वह भी चाहते थे कि बच्चों को बेहतर कोचिंग और सुविधा मिल सके। इसलिए उन्होंने TNM ट्रस्ट के तहत गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी से जमीन लीज पर लेकर वहां पर सुविधा तैयार की। एकेडमी में बेहतर जिम भी है। 2016 में मेरे जन्मदिन पर इस एकेडमी की शुरुआत हुई। अब इस एकेडमी के कई बच्चे रणजी खेल चुके हैं। वहीं आराध्य और सिद्धार्थ का भी चयन अंडर-19 वर्ल्ड कप के लिए इंडिया टीम में हुआ है। अजय शर्मा ने बताया कि सिद्धार्थ के पिता गाजियाबाद में ही परचून की दुकान चलाते हैं।

न्यूज़ ब्रीफ

शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 11 पैसे मजबूत

नई दिल्ली। घरेलू शेयर बाजार में सकारात्मक रुख के बीच भारतीय रुपया बुधवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 11 पैसे बढ़कर 75.48 पर पहुंच गया। कारोबारियों ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और विदेशी पूंजी की निकासी जारी रहने से भी रुपये में वृद्धि सीमित रही। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 75.56 पर खुला, और फिर बढ़त के साथ 75.48 पर पहुंच गया, जो पिछले बंद भाव के मुकाबले 11 पैसे की बढ़त दर्शाता है। पिछले सत्र में अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपया 31 पैसे की मजबूती के साथ 75.59 (अस्थायी) प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। इस बीच छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.05 प्रतिशत बढ़कर 96.54 पर आ गया। वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड वायदा 0.24 प्रतिशत बढ़कर 74.16 डॉलर प्रति बैरल पर था।

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और यू एग्रो के बीच ऋण मुहैया करवाने के लिए समझौता

नई दिल्ली। एक बयान में बताया गया कि उनकी अगले 12 महीने में एमएसएमई क्षेत्र की इकाईयों के बीच 1,000 करोड़ रुपये के ऋण वितरण की योजना है। इसमें बताया गया कि यह ऋण यू एग्रो कैपिटल के प्रथम, संजीवनी, साथी, ग्रो एमएसएमई और मशीनरी फाइनेंसिंग जैसे कार्यक्रमों के तहत एमएसएमई क्षेत्र की विभिन्न इकाईयों को दिया जाएगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक राजीव पुरी ने कहा कि इस समझौते से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को किफायती दरों पर ऋण उपलब्ध करवाया जा सकेगा। यू एग्रो कैपिटल के कार्यकारी अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सचिंद्र नाथ ने कहा कि यह पहली बार है जब इस मंच ने अपने सभी कार्यक्रमों के लिए सह-ऋण प्रदाता समझौता किया है।

फॉक्सकॉन संयंत्र का परिचालन बाधित

चेन्नै। ऐपल के प्रमुख आपूर्तिकर्ता फॉक्सकॉन का चेन्नई के समीप संयंत्र विरोध प्रदर्शन के बाद इस सप्ताह बंद रहेगा। तीन सरकारी सूत्रों ने आज रॉयटर्स को यह जानकारी दी। संयंत्र में विषाक्त खाने 19 दिसंबर को फॉक्सकॉन इंडिया के संयंत्र में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। पुलिस ने दर्जनों लोगों को हिरासत में लिया है। चेन्नई के बाहरी इलाके में स्थित यह फैक्टरी मंगलवार को सुनसान पड़ी थी। फैक्टरी के बाहर कुछ ही कारें दिख रही थीं जिनमें पुलिस के वाहन भी थे। फैक्टरी में दो गार्ड और कुछ सुरक्षा अधिकारियों के अलावा कोई श्रमिक नहीं दिखा।

पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल भारत में बैन

हमारे आईटी नियम तोड़े, यूट्यूब पॉलिसी की भी उड़ाई धज्जियां

क्रिएटर्स के तौर पर आप नहीं करें ऐसी गलती

आईटीडीसी इंडिया ई-प्रेस/ आईटीडीसी न्यूज नई दिल्ली

सरकार ने पाकिस्तान की 2 वेबसाइट और 20 यूट्यूब चैनल के ऊपर कैंची चलाई है। ये भारत में फेक न्यूज फैला रहे थे। साथ ही देश विरोधी गतिविधियों का अंजाम भी दे रहे थे। देश की इंटेलिजेंस एजेंसियों और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के इनकी पहचान की थी। ये सभी पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे थे। इन पर कश्मीर, भारतीय सेना, अल्पसंख्यक समुदाय, राम मंदिर, CDS जनरल बिपिन रावत, कृषि कानूनों, CAA के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर भड़काऊ पोस्ट आ रहे थे। पाकिस्तान से चल रहे यूट्यूब चैलन और वेबसाइट पर बैन इसलिए लगाया गया क्योंकि वे फेक कंटेंट को पोस्ट कर रहे थे। इस तरह के कंटेंट को लेकर यूट्यूब की पॉलिसी क्या कहती है क्या सरकार चाहे तो आपके यूट्यब चैनल को बैन कर सकती है आखिर किन-किन गलतियों की वजह से यूट्यूब चैनल पर बैन लगाया जा सकता है इन तमाम सवालों के जवाब जानते हैं।

कंटेंट क्रिएटर के लिए यूट्यूब की पॉलिसी क्या कहती है

गूगल ने यूट्यूब कंटेट क्रिएटर और चैलन चलाने वालों के लिए एक पॉलिसी बनाई है, जो उसके support.google.com पर दी है। इस पॉलिसी के मुताबिक, आप यूट्यूब से कमाई कर रहे हैं, तो यह जरूरी है कि आपका चैनल, यूट्यूब पर कमाई करने से जुड़ी पॉलिसी को फॉलो करता हो। पॉलिसी में यूट्यूब के कम्यूनिटी दिशा-निर्देश, सर्विस की कंडीशन, कॉपीराइट और गूगल एडसेंस प्रोग्राम की पॉलिसी शामिल हैं। ये पॉलिसी उन लोगों पर लागू होती हैं जो यूट्यूब पार्टनर कार्यक्रम में शामिल हैं या शामिल होना चाहते हैं। आप अपने वीडियो पर विज्ञापन दिखाने की सर्विस ऑन करके कमाई करना चाहते हैं, तो यह जरूरी है कि वे विज्ञापन देने वालों के लिहाज से अच्छे वीडियो बनाने के गाइडलाइन के मुताबिक हों। इस बात को पक्का करें कि आपने हर पॉलिसी को अच्छी तरह पढ़ लिया है, क्योंकि इन पॉलिसी से ही तय किया जाता है कि किसी चैनल पर कमाई करने की सुविधा दी जा सकती है या नहीं।

यूट्यूब के कम्यूनिटी गाइडलाइन का फॉलो नहीं किया तब क्या होगा

कम्यूनिटी गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले वीडियो से कमाई नहीं कर पाएंगे। उसे प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाएगा। यूट्यूब से कमाई करने वाले क्रिएटर्स को यह पता होना चाहिए कि दिशा-निर्देश, किसी खास वीडियो पर ही नहीं, बल्कि पूरे चैनल पर लागू होते हैं। ऐसे में क्रिएटर को इन तमाम बातों का ध्यान रखना जरूरी है। यदि आप कंटेंट क्रिएटर के तौर पर यूट्यूब की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हैं, तो न सिर्फ आप उस वीडियो से पैसे नहीं कमा पाएंगे, बल्कि आपके चैनल पर भी बैन लगा दिया जाएगा। फिर जब तक उसका रिव्यू नहीं किया जाता वो बैन ही रहेगा। यूट्यूब अपनी गाइडलाइन को लेकर काफी सख्ती दिखाता है। भारत सरकार ने इसी साल 26 मई से नए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) नियम, 2021 लागू किए हैं।

2021 में काम के मोर्चे पर राहत और चुनौतियां दोनों रहीं

आईटीडीसी इंडिया ई-प्रेस/ आईटीडीसी न्यूज नई दिल्ली

एक और मुश्किल वर्ष पलक झपकते ही गुजर गया। ऐसा साल, जिसमें हालात बदलते रहे और इस दौरान हम आशा और निराशा के बीच झूलते रहे और अब इन दोनों के कहीं बीच में हैं। जनवरी 2021 कोविड टीके की उम्मीद लेकर आया और आंशिक स्तर पर कार्यालयों में लौटने की संभावना दिखाई दी। कार्यालय की चर्चा में %हाइब्रिड% का विचार यानी कुछ कर्मचारियों का कार्यालय से और कुछ का घर से काम करना प्रमुख बन गया। जब विभिन्न क्षेत्रों के संगठनों ने करीब एक साल तक घर से काम के बाद कर्मचारियों को दफ्तर वापस बुलाने का इंतजाम शुरू किया तो डेल्टा स्वरूप ने उनकी सभी योजनाओं पर पानी फेर दिया। अब डर और दुख के बीच एक बार फिर निराशा गहरा रही है। भारत में कोविड संक्रमण का पहला मामला आने के करीब एक साल बाद जनवरी में कृष्ण जी इन्सान अपने दफ्तर लौट चुके थे, जबकि उस समय ज्यादातर कंपनियों में वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। इसकी वाजिब वजह भी थी। इन्सान असम में ऑयल इंडिया लिमिटेड के वरिष्ठ प्रबंधक हैं, इसलिए उनका क्षेत्र आवश्यक सेवा क्षेत्र है। वह रोजाना दफ्तर जाते थे, लेकिन सुरक्षा की खातिर सहयोगियों के साथ ज्यादातर वर्चुअल बैठकें करते थे। उस समय उन्होंने इस संवाददाता को बताया था, टीके का बहुत ज्यादा इंतजार है। आज 11 महीने बाद डेल्टा स्वरूप जा चुका है और एक अरब से अधिक भारतीयों को टीके लग गए हैं और उन जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के लोगों का पूर्ण टीकाकरण हो गया है। वह कहते हैं कि लोगों ने कोविड नियमों का पालन करते हुए फिर से साहस जुटाया है। वह हाल में दक्षिण कोरिया में जी20 लीडरशिप सम्मेलन से लौटे हैं, जिसमें 15 देशों के 22 लोगों को आमंत्रित किया गया था। उन्हें पूरा भरोसा है कि वर्ष 2022 में कारोबारी यात्रा ठीक से होने लगेंगी। वह कहते हैं, दुबई एक्सपो पहले ही में हमें इसकी झलक दे चुका है। उन्होंने उम्मीद जताई कि कोरोनावायरस के नए स्वरूप ओमीक्रोन से स्थितियां नहीं बिगड़ेंगी।

चढ़ते बाजार में शेयर गिरवी से परहेज

आईटीडीसी इंडिया ई-प्रेस/ आईटीडीसी न्यूज मुंबई

मौजूदा रुझानों को देखते हुए ऐसा लगता है कि शेयरधारकों ने कर्ज का बोझ कम करने के लिए शेयर गिरवी रखने की कवायद कम कर दी है। इससे पहले वे कर्ज से निपटने के लिए पहले वे अपने शेयर गिरवी रख रहे थे मगर अब इस चलन में कमी देखी जा रही है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने जिन कंपनियों का विश्लेषण किया है उनके द्वारा गिरवी रखे गए शेयरों का कुल मूल्य भले ही अधिक हो गया है मगर यह उनके बाजार पूंजीकरण के हिस्से के लिहाज से कम है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जिन कंपनियों ने अपने शेयर गिरवी रखे थे उन्होंने बाजार चढ़ने के समय इन्हें भुनाने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने शेयर गिरवी रख कर भारी मात्रा में रकम उधार लेने से परहेज किया। यह विश्लेषक 953 कंपनियों के एक नमूने पर आधारित है। शेयरधारकों ने शेयर गिरवी रखे थे जो सितंबर 2017 तक उनके कुल बाजार पूंजीकरण के 5 प्रतिशत हिस्से के बराबर थे। इससे पता चलता है कि तब से इसमें लगातार गिरावट आई है। यह सितंबर 2021 तक कम होकर बाजार पूंजीकरण के 4.1 प्रतिशत हिस्से के बराबर रह गया था। प्रवर्तक एवं अन्य शेयरधारक अपने शेयर कर्जदाता के पास गिरवी रखकर रकम जुटा सकते हैं। नियमों के अनुसार कंपनियों को गिरवी रखे गए शेयरों की जानकारी सार्वजनिक रूप से देनी होती है। 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद यह प्रावधान आया है। जिन कंपनियों के अधिक शेयर गिरवी रखे गए हैं अगर प्रवर्तक कर्जदाताओं को ऋण भुगतान करने में असफल रहते हैं तो इससे उन कंपनियों के शेयरों की कीमतों पर प्रतिकूल असर होता है। कर्जदाता बड़े पैमाने पर शेयर बेच देते हैं जिनसे शेयर कीमतें कम हो जाती हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने वर्ष 2019 में खुलासा नियम फिर कड़े कर दिए थे। ऐसा कहा गया कि कुछ प्रवर्तक अपने शेयर गिरवी रखने के लिए दूसरी तरकीब आजमा रहे हैं। नियमों में बदलाव पर 2019 में सेबी के दिशानिर्देशों में कहा गया था, हाल में ऐसे कुछ उदाहरण देखने में आए हैं । जिनमें सूचीबद्ध कंपनियों के प्रवर्तक के नियंत्र वाली प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां प्रवर्तकों द्वारा समर्थित डिबेंचर जारी करती हैं। ये डिबेंचर किसी समूह कंपनी के गिरवी शेयरों या देनदारी आदि रूपों में होते हैं। ये काफी पेचीदा होते हैं। अधिग्रहण नियमों का मकसद सभी प्रकार की देनदारी पर नजर रखना है। इस लिहाज से इस बात की जरूरत महसूस की जा रही है कि ऐसी देनदारी का दायरा और स्पष्ट किए जाने की जरूरत हैं। मोटे तौर पर उधार लेने के लिए एक छोटी हिस्सेदारी गिरवी रखी जाती है मगर अलग-अलग क्षेत्रों में शेयर गिरवी रखने की प्रक्रिया तेज हो गई थी। नमूने की 953 कंपनियां 69 विभिन्न क्षेत्रों से थीं। जितने मूल्य के शेयर गिरवी रखे गए थे उनमें शीर्ष पांच कंपनियों की हिस्सेदारी 54.7 प्रतिशत थी। सितंबर 2019 के बाद खान एवं खनिज उत्पादों में तेजी देखी गई। उस समय गिरवी रखे शेयरों में इनका हिस्सा 0.1 प्रतिशत से कम था। मगर अब इनकी हिस्सेदारी बढ़कर 21.4 प्रतिशत हो गई है।

स्पिनी ने 1.2 करोड़ डॉलर के ईसॉप्स की खरीद पूरी की

आईटीडीसी इंडिया ई-प्रेस/ आईटीडीसी न्यूज बेंगलूरु

इस महीने यूनिकॉर्न बनी पुरानी कारों की खरीद-बिक्री प्लेटफॉर्म स्पिनी ने मौजूदा व पूर्व कर्मियों से 1.2 करोड़ डॉलर की ईसॉप्स खरीद पूरी कर ली है। कंपनी की तरफ से ईसॉप्स की यह पहली पुनर्खरीद थी। स्पिनी के संस्थापक व सीईओ नीरज सिंह ने कहा, ईसॉप्स कोष इसलिए बनाया गया ताकि हमारी टीम के सदस्यों का स्पिनी के विजन पर भरोसा और इस विजन को वास्तविकता में तब्दील करने की खातिर उनकी कड़ी मेहनत का ईनाम देना सुनिश्चित हो। हमारा शुरू से ही एक ऐसा संस्थान बनाना चाहते हैं जो हमारे हर खरीदारों को पूरी पारदर्शिता और बेहतर अनुभव उपलब्ध कराए और इस तरह से हम ग्राहकों का भरोसा हासिल कर सकें। स्पिनी ने ई-सीरीज की फंडिंग के तहत 28.3 करोड़ डॉलर नए व मौजदा निवेशकों से इस महीने जुटाए। इसकी अगुआई अबु धाबी की एडीक्यू, टाइगर ग्लोबल और अवनीर ग्रोथ ने की।

PRESS ITDC
ITDC NEWS
www.itdcindia.com

मध्य भारत से विश्वसनीय हिन्दी दैनिक समाचारपत्र
आईटीडीसी न्यूज़,

विश्वसनीयता की अपेक्षा पर खरा बनाने के लिए हम निरंतर कार्य कर रहे हैं,
प्रति सप्ताह आप सभी का स्वागत

मेरे लोग, मेरा विधान

इसके तहत हम आप सभी से अनुरोध कर रहे हैं कि
विश्लेषणात्मक रचनाएं, जनसामान्य हित में
नई जानकारियां, लेख, आलेख, टीका, विवेचना, समाचार, रोचक तथ्य,
नए प्रयास, अभिनव प्रयोग के रूप में हमें प्रेषित करें।

आपकी रचना, नाम, चित्र सहित, अधिकाधिक पाठकों तक पहुंचे,
इसके लिए हम, समाचार पत्र में प्रकाशित रचनाओं को,
देश के सभी प्रचलित सोशल मीडिया स्टैंड जैसे फेसबुक, लिंक्डीन, यूट्यूब, जीटॉक, ट्विटर, इंस्टाग्राम
व्हाट्सएप्प एवं हमारे डिजिटल स्टैंड से प्रचार-प्रसार भी देंगे।
(दीर्घ समय तक https://www.itdcindia.com/saga-news.php पर भी उपलब्ध)
जिससे लाभान्वित जनों की संख्या निरंतर बढ़ती रहे।

आप सभी इच्छुकजन अपनी गैरमानदेय,
अपठित, नवीन, मूल एवं मौलिक रचना, हिन्दी में हमें प्रेषित करें।
(और अंग्रेजी में भेजने पर केवल हमारे डिजिटल स्टैंड पर ही प्रकाशन होगा)
उक्त हेतु, आपका चित्र, नाम, शहर, मोबाइल न, आपकी रचना, मेल करें-ईमेल
itdcnewsmp@gmail.com

इंटीग्रेटेड ट्रेड डेवलपमेंट सेंटर न्यूज़

महंगे पेट्रोल- डीजल और खुद की बढ़ती जरूरत से लोगों के फाइनेंस को लेकर व्यवहार में आया बड़ा बदलाव

आईटीडीसी इंडिया ई-प्रेस/ आईटीडीसी न्यूज नई दिल्ली

पेट्रोल-डीजल की आसमान छूती कीमतें और महामारी के बीच खुद के घर की जरूरत महसूस होने से देश में फाइनेंस को लेकर व्यवहार में बड़ा बदलाव आया है। फ्यूल कार्ड्स जैसे खास क्रेडिट कार्ड्स की डिमांड करीब 10 गुना बढ़ गई है। देश में इस्तेमाल हो रहे कुल क्रेडिट कार्ड में फ्यूल कार्ड्स की हिस्सेदारी बढ़कर 13.1 फीसदी हो गई है, जो बीते साल 4.95 फीसदी थी। अब सारे दफ्तर और स्कूल-कॉलेज खुल गए हैं, लिहाजा निकट भविष्य में भी फ्यूल कार्ड्स की जोरदार डिमांड बनी रहेगी। बैंक बाजार की मनीमूड रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल क्रेडिट कार्ड्स इस्तेमाल करने वाली महिलाओं की संख्या करीब 50 फीसदी बढ़ी है। देश के कुल क्रेडिट कार्ड यूजर्स में महिलाओं की संख्या 12 फीसदी हो गई, जबकि 2020 में यह आंकड़ा 8.41 फीसदी था। किशोरियां ज्यादा क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रही हैं। होम लोन के मामले में भी इस साल बड़ा बदलाव आया है। 2021 की पहली तिमाही में होम लोन का औसत साइज बढ़कर 28.43 लाख रुपए हो गया, जो 2020 की चौथी तिमाही में 27.74 लाख रुपए था। इसके बाद कोविड महामारी की दूसरी लहर के दौरान इस मामले में थोड़ी कमी आई, लेकिन साल की तीसरी तिमाही के बाद से रिकवरी शुरू हो गई।

क्रेडिट स्कोर मजबूत रखने में महिलाएं पुरुषों से ज्यादा संजीदा

अब हालात ऐसे हो गए हैं कि देश में डेढ़ करोड़ रुपए से भी ज्यादा बड़े लोम लोन की डिमांड निकलने लगी है। मनीमूड रिपोर्ट के मुताबिक, फाइनेंशियल हैबिट्स के मामले में पुरुषों से महिलाएं ज्यादा सतर्क हैं। इस साल 72 फीसदी महिलाओं का क्रेडिट स्कोर 700 या इससे ज्यादा रहा, जबकि इतना क्रेडिट स्कोर वाले पुरुषों की तादाद 66 फीसदी है। यही नहीं, जहां 40 फीसदी महिलाओं का क्रेडिट स्कोर 800 से ऊपर रहा, वहीं इतना स्कोर वाले पुरूष 35.6 फीसदी ही रहे।

इंटीग्रेटेड ट्रेड डेव्हेलपमेंट सेंटर न्यूज़ के लिए मालिक, मुद्रक एवं प्रकाशक राधिका वीरेंद्र, स्वामी- इंटीग्रेटेड ट्रेड डेव्हेलपमेंट सेंटर इंडिया ईप्रेस द्वारा साई प्रिंटर्स, 91, जहांगीराबाद, भोपाल से मुद्रित करवाकर, श्री परिसर, 23 पश्चिम निशातपुरा, डीआईजी बंगला, भोपाल से प्रकाशित। संपादक- राधिका वीरेंद्र आरएनआई क्र. MPHIN/2018/77221, 0755-4223334 पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार।